

अनुगामिनी

विपक्ष को एकजुट करना ही हमारा लक्ष्य : नीतीश 3 सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास 7

मूसलाधार बारिश से पश्चिम सिक्किम में भारी नुकसान पूर्वोत्तर में सही नेताओं का प्रतिनिधित्व जरूरी : भाइचुंग



अनुगामिनी नि.सं.

गेंजिंग, 06 सितम्बर । बीती रात को हुई मूसलाधार बारिश के कारण पश्चिम सिक्किम जिला के विभिन्न स्थानों में व्यापक नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण लेगसेप गेंजिंग सड़क के बीच ओमचुंग चार माइल रानी खोल्सा में उफान के कारण सड़क बंद हो गयी थी। वहीं रानीवन में भी खोला के पानी से सड़क को काफी क्षति पहुंची है। रात भर इस सड़क पर आवागमन पूरी तरह ठप रहा। इसके कारण स्थानीय लोगों एवं स्कूली छात्र-छात्राओं को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। आज दोपहर बाद इस सड़क पर आवागमन सुचारू हो गया है और वाहनों की आवाजाही शुरू हो गयी है। वहीं लिंगचोम-गेंजिंग सड़क लिगजेक में क्षतिग्रस्त हो जाने के

कारण वहां आवागमन बंद होने के कारण, 06 सितम्बर । गेंजिंग जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली विभिन्न सड़कों का भी यही हाल है। उधर रिचनपोंग समष्टि के अपर हाथीदुंगा गांव में भी बारिश एवं भूस्खलन से दो घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें अपर हाथीदुंगा के कृष्ण कुमार तमांग और लाक्पा तमांग के घर शामिल हैं। इन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। क्षेत्रीय प्रभारी फुवां छिरिंग भूटिया तथा स्थानीय पंचायत ने ग्रामीणों के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इसी तरह भारी बारिश के कारण गेंजिंग-बर्मेक समष्टि के रंगतु निवासी नरपति शर्मा के कच्चे घर को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं आज सवेरे गेंजिंग करपर समेत विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली सड़क के साथ ही खेतों, इलाहची बाड़ी, मक्का



बाड़ी आदि को भी नुकसान पहुंचा है। इधर भूस्खलन के कारण आज गेंजिंग से सिलीगुड़ी, गंगटोक, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जोरथांग एवं अन्य स्थानों के बीच वाहनों की आवाजाही बंद हो गयी। हालांकि इसमें जान-माल की कोई क्षति न होने के बावजूद सड़क, पुल आदि को व्यापक नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि नया बस्ती, तिकजुक, सेंट मैरी स्कूल, डाइट कॉलेज, भानु सालिग क्षेत्र, यांगथांग, यांगते, अपर सिंगयांग, बर्थांग, मियोंग और भातुथांग गांव हैं।

जिला कलेक्टर के नेतृत्व में जिला अधिकारियों की टीम ने दिन में प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने अवरुद्ध सड़कों और झोराओं को तुरंत साफ करने का निर्देश दिया और सभी प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपायों के रूप में तिरपाल और पॉली पाइप प्रदान किए। उन्होंने आवश्यकतानुसार आगे भी मदद का आश्वासन दिया गया। प्रभावित स्थानों का दौरा करने वाली निरीक्षण टीमों में एडीसी, ग्यालशिग, एसडीएम ग्यालशिग, एसडीएम

(पीएमजीएसवाई) और टीम, डीपीओ (डीडीएमए) के साथ त्वरित राहत दल और वन और सड़क और पुल विभाग के अधिकारी शामिल थे। प्रभावित स्थानों का दौरा करने के बाद, डीसी गेंजिंग ने तत्काल बहाली के लिए एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने अगले 07 दिनों में मौजूदा सड़क को बनाए रखने के लिए प्लम वॉल / गेबियन वॉल के निर्माण का प्रस्ताव दिया है और साथ ही नए आरसीसी गर्डर बीम को फिर से बनाने को भी कहा।

पूर्वोत्तर में सही नेताओं का प्रतिनिधित्व जरूरी : भाइचुंग



अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 06 सितम्बर । अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष पद के चुनाव में मिली हार के बाद भाइचुंग भूटिया ने आज मंगलवार को पूर्वोत्तर के नेताओं को लोगों के लिए सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की चुनौती दी। भूटिया का सिक्किम के विभिन्न राजनीतिक प्रतिनिधियों सहित उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने भव्य स्वागत किया।

भूटिया ने हालांकि अपने एआईएफएफ चुनाव हार के विवरण में जाने से इंकार किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे कल मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि, मीडिया द्वारा किए गए सवालियों की झड़ी पर भाइचुंग भूटिया ने पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हमारा प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वे पूर्वोत्तर के नेता हैं लेकिन हम स्पष्ट रूप से देखते

हैं कि उनकी रुचि राजनीतिक लाभ में हैं पूर्वोत्तर में नहीं। भाइचुंग भूटिया ने पूर्वोत्तर के लोगों से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सही नेताओं का चयन करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि हमने पूरे देश को दिखाया है कि परिणाम कुछ भी हो सिक्किम के लोग एकजुट हो सकते हैं और सिर्फ सिक्किम ही नहीं, बल्कि पूरा पूर्वोत्तर एकजुट हो सकता है। पूर्वोत्तर के लोगों के लिए सही लोगों का चयन करने का समय आ गया है। सिक्किम के लोगों से मिले भारी समर्थन पर हार्मो सिक्किम पार्टी के नेता ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता को केंद्र में लोगों को ले जाने की जरूरत है जो हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकें, वे सिर्फ यह कहकर नहीं रह सकते कि वे हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तविकता यह है कि वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों को ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है।

सिक्किम का नाम रौशन करें खिलाड़ी : मंत्री शर्मा



अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 06 सितम्बर । सिक्किम स्टेट कराटे टू एसोसिएशन के तत्वावधान में आज गंगटोक के इंडोर जिम्नेजियम सभागार में 18वें स्टेट कराटे प्रतियोगिता का शुभारम्भ हुआ। उद्घाटन समारोह में राज्य के कृषि व बागवानी मंत्री लोक नाथ शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। बताया गया कि प्रतियोगिता में सब-जूनियर, जूनियर एवं सीनियर स्तर के तीन विभागों में पूरे राज्य भर के तीन सौ से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 7 सितम्बर तक चलेगी। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता के विजेताओं को इसी

स्टेट कराटे प्रतियोगिता का शुभारंभ वर्ष अक्टूबर में शिलोंग में आयोजित होने वाली दूसरी नॉर्थ-ईस्ट ओलिम्पिक गेम्स में शिरकत करने का अवसर प्राप्त होगा। आज प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्य अतिथि लोक नाथ शर्मा ने राज्य की उभरती प्रतिभाओं को यह मंच प्रदान कर अपनी प्रतिभा दर्शाने का अवसर देने हेतु आयोजक संस्था को धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने प्रतियोगिता (शेष पृष्ठ 03 पर)

चुंगथांग में सिविल जज सह न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का उद्घाटन

अनुगामिनी नि.सं. मंगन, 06 सितम्बर । सिविल जज-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का उद्घाटन समारोह आज मंगन जिले के चुंगथांग सब डिवीजन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले), सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विश्वनाथ सोमहर, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती मीनाक्षी मदन राई, सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान, कानून और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा, भवन एवं आवास विभाग के मंत्री संजीत खरेल, सड़क एवं पुल एवं संस्कृति विभाग के मंत्री साम्पु लेप्चा, मंत्री वन पर्यावरण और वन्यजीव विभाग कर्मा लोदे, जिला अध्यक्ष सुश्री निन्दे लेप्चा, डीसी मंगन डॉ एबी कार्की, एडीसी मंगन, एसपी मंगन, एडीसी देव चुंगथांग, एसडीएम चुंगथांग, एसडीपीओ चुंगथांग, जिला और



सत्र न्यायालय के अधिकारी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी के छात्रों द्वारा स्काटिश मार्चिंग बैंड के प्रदर्शन के साथ मेहमानों के स्वागत के साथ हुई। स्कूल, मंगन के बाद गणमान्य व्यक्तियों द्वारा खड़े और गुलदस्ते और दीप प्रज्वलित किए गए। इसके बाद न्यायालय कक्षा का उद्घाटन किया गया और अधिकारियों ने नव स्थापित बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमाहर ने सभा को संबोधित करते हुए एक पूर्ण

न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थापना का उल्लेख किया, जो न केवल जिले के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मील का पत्थर है। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद और बधाई दी और राज्य के नागरिकों के लिए न्याय तक आसान पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने अपने संबोधन में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में समर्पण और योगदान के लिए न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमहर को धन्यवाद दिया और भवन निर्माण में लगे सभी लोगों को बधाई दी।

खेलो इंडिया सेंटर के गठन के लिए बैठक आयोजित



अनुगामिनी नि.सं.

सोरेंग, 06 सितम्बर । 14 वर्ष से कम उम्र के लड़के-लड़कियों के बैडमिंटन खेल में खेलो इंडिया सेंटर के गठन हेतु आज स्थानीय स्टेट स्पोर्ट्स अकाडमी में एक बैठक आयोजित की गयी। इसमें सोरेंग जिला एडीसी (विकास) गायस पेगा, एसडीएम मुख्यालय डीआर बिस्ट के अलावा

जिला परिषद डीपीओ दिलीप शर्मा, बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव पारु हांग सुब्बा, एसवाईए के डिप्टी डायरेक्टर दिलीप कुमार छेत्री, एसवाईए के सहायक निदेशक-1 श्रीमती ममता गुरुंग, सहायक निदेशक-2 पाल्देन भूटिया के साथ ही विशेष शिक्षा अधिकारी एसबी सुब्बा एवं अन्य मौजूद रहे। जिला खेल व युवा (शेष पृष्ठ 03 पर)

पशुपालन सचिव मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटियों का किया दौरा

अनुगामिनी का.सं. गंगटोक, 06 सितम्बर । सिक्किम में दूध उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर हेतु सिक्किम मिल्क यूनियन ने कई कदम उठाये हैं। यूनियन के अधिकारी केवल गुणवत्तापूर्ण दूध संग्रह के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस दिशा में यूनियन द्वारा नियमित रूप से प्राथमिक दुग्ध सहकारिताओं के साथ मिलकर जागरूकता एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य के पशुपालन सचिव एवं सिक्किम मिल्क यूनियन के प्रबंध निदेशक पी सेंथल कुमार ने सम्बंधित विभाग के अधिकारियों

के साथ लोअर, लालमू, कामरे तथा सेन्ट्रल पानदेम साजोंग मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का दौरा किया और वहां दूध जांच तथा कूलिंग सुविधाओं के साथ अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। उनके साथ सम्बंधित प्रोक्वोरमेंट ऑफिसर पूरण और रूटी फील्ड सुपरवाइजर बिमल राई भी थे। इस दौरान उनलोगों ने सोसाइटी के परिचालन के साथ ही दूध के ससमय भुगतान तथा सहायता राशि भुगतान के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान श्री कुमार ने सोसाइटी के भुगतान रजिस्टर की भी जांच की और कर्मचारियों को दूध की गुणवत्ता तथा मात्रा बढ़ाने का निर्देश



दिया। साथ ही उन्होंने मिल्क यूनियन द्वारा दिये गये उपकरणों की समुचित रखरखाव के बारे में भी कहा। इस अवसर पर उन्होंने किसानों द्वारा उत्पादित दूध की गुणवत्ता बढ़ाने

को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यूनियन की ओर से दूध की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सभी प्रयास किये जा रहे हैं। बाजार में (शेष पृष्ठ 03 पर)

मंत्री शर्मा ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ की परिचयात्मक बैठक



अनुगामिनी का.सं. गंगटोक, 06 सितम्बर । सिक्किम के कृषि, बागवानी तथा श्रम विभाग के मंत्री लोक नाथ शर्मा ने आज श्रम भवन में विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के

साथ एक परिचयात्मक बैठक की। इस दौरान राज्य के ऊर्जा व परिवहन मंत्री एमएन शेरपा विशेष रूप से उपस्थित रहे। गौरतलब है कि हाल ही में मंत्री शर्मा ने श्रम (शेष पृष्ठ 03 पर)

नई ऊंचाई छुएंगे भारत-बांग्लादेश के रिश्ते, आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने शेख हसीना से मांगा सहयोग

नई दिल्ली, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना चार दिवसीय भारत यात्रा पर है। उन्होंने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारत ने शेख हसीना का जोरदार स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत बांग्लादेश एक प्रमुख भागीदार रहा है। हम आपसी सहयोग से दोनों देशों के लोगों की आजीविका में निरंतर सुधार कर रहे हैं। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी समेत तमाम सेक्टरों की तरफ कदम बढ़ाए हैं। अगले 25 वर्षों में भारत-बांग्लादेश संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी और शेख हसीना की आतंकवाद, कट्टरवाद और जलवायु परिवर्तन समेत समेत

वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि यह जरूरी है कि हम एक साथ उन ताकतों का सामना करें जो हमारे खिलाफ हैं। इससे पहले सोमवार को दिल्ली पहुंचीं शेख हसीना का कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने स्वागत किया। उन्होंने द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की और दिल्ली में एक प्रमुख तीर्थस्थल पर्यटक आकर्षण निजामुद्दीन औलिया दरगाह का दौरा किया।

पीएम मोदी पिछले साल बांग्लादेश की आजादी के 50वें वर्ष के मौके पर बांग्लादेश पहुंचे थे। उसके बाद शेख हसीना की यह पहली भारत यात्रा है। पीएम मोदी ने कहा अगले 25 वर्षों में भारत-बांग्लादेश संबंध नई ऊंचाइयों पर

पहुंचेंगे। इस दौरान शेख हसीना ने कहा, 'अगले 25 वर्षों के लिए मैं अमृत काल की नई सुबह के लिए शुभकामनाएं देती हूँ क्योंकि, आत्मनिर्भर भारत के साथ बांग्लादेश विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्राप्त कर आगे बढ़ रहा है।'

पीएम नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया। कहा, 54 नदियां भारत-बांग्लादेश सीमा से होकर बहती हैं जो दोनों देशों के लोगों की आजीविका से जुड़ी हैं। आज, हमने कुशियारा नदी के जल-बंटवारे के संबंध में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि कुशियारा नदी जल बंटवारे से दक्षिण असम और बांग्लादेश का सिलहट क्षेत्र लाभान्वित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत



की 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत बांग्लादेश एक प्रमुख भागीदार रहा है। भारत और बांग्लादेश ने भूमि और समुद्री सीमा सीमांकन, सुरक्षा, संपर्क, विकास सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शक्ति और ऊर्जा, व्यापार और वाणिज्य, अर्थव्यवस्था और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्राप्त किए हैं।

शेख हसीना के बीच महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद सिर्फ एक देश नहीं वैश्विक चिंता का विषय है। हमने आतंकवाद पर भी चर्चा की है। यह जरूरी है कि हम एक साथ उन ताकतों का सामना करें जो हमारे खिलाफ हैं।

कार की पिछली सीट पर भी बेल्ट लगाना होगा अनिवार्य, गडकरी बोले- नियम नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अब होगा अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही। इस हदसे पर नितिन गडकरी ने भी खेद व्यक्त किया है।

गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय उन लोगों पर जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है जो लोग कार में बिना सीट बेल्ट लगाए सफर करते हैं, भले ही वे आगे या पीछे किसी भी सीट पर बैठे हों। अब उन पर जल्द भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित आईएए ग्लोबल समिट में पहुंचे गडकरी ने साइरस मिश्री के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब दिए।

गडकरी ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, फिर भी उन्होंने प्रस्तावित नए सीट बेल्ट नियम के उद्घाटन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि को बताने से इनकार कर दिया। हालांकि,



उन्होंने कहा कि कार बनाने समय एयरबैग को अनिवार्य बनाने के प्रावधान के साथ नए नियम की कारों को तैयार किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में सड़क दुर्घटना में टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिश्री की मौत के बाद सवाल उठने लगे हैं कि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है। इस हदसे की जांच कर रही पुलिस ने बताया है कि साइरस ने दुर्घटना के वक्त सीट बेल्ट नहीं पहनी थी।

उन्होंने कहा कि देश में 1 साल के अंदर 500,000 दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड देखकर दंग रह गया हूँ। गडकरी ने बताया कि सड़क हादसों में 60 प्रतिशत 18-34 आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। उन्होंने ग्रामीण आबादी के शहरी क्षेत्रों में

भारी प्रवास पर अफसोस जताया और कहा कि आज गांवों और वन क्षेत्रों में 65 प्रतिशत लोग सकल घरेलू उत्पाद के 12 प्रतिशत से अधिक का योगदान नहीं करते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम (1989) की धारा 138 (3) के अनुसार आप जिस कार में नियम 125 या नियम 125 के उप-नियम (1) या उप-नियम (1-ए) के तहत सीटबेल्ट दी जाती है। किसी कार में चालक और आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। साथ ही 5 सीट कारों में पीछे बैठने वाले यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। वहीं 7 सीट कार जिसमें पीछे बैठे यात्रियों का चेहरा सामने की तरफ होता है, उसमें चलते समय सीट बेल्ट लगाना जरूरी है।

भारत और बांग्लादेश के आपसी विश्वास पर हमला करने वाली ताकतों का मिलकर मुकाबला करना होगा: मोदी



नई दिल्ली, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत और बांग्लादेश को मिलकर उन आतंकवादी तथा चरमपंथी ताकतों का सामना करना होगा जो दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास पर हमला कर सकती हैं।

मोदी ने भारत यात्रा पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से द्विपक्षीय वार्ता के बाद यह बात कही। हसीना ने इस दौरान तीस्ता जल बंटवारे को लेकर जल्द समाधान पर पहुंचने की पुर्जोर वकालत की। मोदी ने कहा कि आज हमने आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की भावना को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसी ताकतों का मिलकर सामना करें जो हमारे आपसी विश्वास पर हमला करती हों।

भारत और बांग्लादेश ने मोदी और हसीना की वार्ता के बाद सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये जिनमें एक कुशियारा नदी के जल बंटवारे से संबंधित भी है जो दक्षिणी असम के क्षेत्रों और बांग्लादेश के सिलहट इलाके को लाभान्वित कर सकता है। मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश की सीमाओं से 54 नदियां गुजरती हैं और ये सदियों से दोनों देशों के लोगों की आजीविका से जुड़ी हैं। हसीना ने यहां हैदराबाद हाउस में संयुक्त मीडिया वार्ता में कहा कि दोनों देशों ने मित्रता और सहयोग की भावना से अनेक मुद्दों का समाधान किया है। हमें आशा है कि तीस्ता जल बंटवारा समझौते समेत सभी लंबित मुद्दों को जल्द निपट लिया जाएगा।

भारत-बांग्लादेश की यारी चीनी मंसूबों पर भारी, बढ़ रही हैं ड्रैगन की मुश्किलें

नई दिल्ली, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। भारत के कूटनीतिक प्रयासों व बांग्लादेश की दोस्ती सबसे और बैर किसी से नहीं नीति के चलते चीन तमाम प्रयासों के बावजूद वहां सामरिक निवेश नहीं कर पाया है। आज भले ही चीन वहां खूब निवेश कर रहा हो, बावजूद बांग्लादेश और भारत के व्यापारिक, सामरिक और राजनीतिक रिश्ते लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं।



भारत यात्रा पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी भारत को आश्चर्य किया है कि दोनों देशों के रिश्ते किसी तीसरे देश की उपस्थिति से कतई प्रभावित नहीं होने दिए जायेंगे। सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेश में चीन द्वारा 40 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश किया गया है या प्रक्रिया में है। जबकि भारत का निवेश इसका करीब आधा ही है।

चीनी निवेश के साथ कुछ और भी दिक्कतें हैं जैसे चीन अपने निवेश के साथ-साथ अपने कार्मिक भी वहां भेजता है, जबकि भारत के निवेश के मामले में ऐसा नहीं है। भारत के बांग्लादेश के साथ चार रेल मार्ग और सड़क संपर्क भी बना हुआ है। भारत के निवेश से वहां बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार भी सृजित हो रहा है। इसलिए बांग्लादेश भारत के साथ निवेश बढ़ाने का कहीं ज्यादा इच्छुक है।

बांग्लादेश से व्यापार के मामले में चीन और भारत की स्थिति

के जीवन को बेहतर बनाना है। लेकिन चीनी निवेश पर बांग्लादेश उतना सहज भी नहीं है। सूत्रों की मानें तो श्रीलंका में उत्पन्न आर्थिक संकट के बाद बांग्लादेश इस दिशा में थोड़ा सतर्क भी हुआ है। चीनी निवेश के साथ कुछ और भी दिक्कतें हैं जैसे चीन अपने निवेश के साथ-साथ अपने कार्मिक भी वहां भेजता है, जबकि भारत के निवेश के मामले में ऐसा नहीं है। भारत के बांग्लादेश के साथ चार रेल मार्ग और सड़क संपर्क भी बना हुआ है। भारत के निवेश से वहां बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार भी सृजित हो रहा है। इसलिए बांग्लादेश भारत के साथ निवेश बढ़ाने का कहीं ज्यादा इच्छुक है।

बांग्लादेश से व्यापार के मामले में चीन और भारत की स्थिति करीब-करीब बराबरी की है जबकि चीन ने अपने ज्यादातर उत्पादों को बांग्लादेश के लिए कर मुक्त कर रखा है। भारत ने अभी तक ऐसा नहीं किया है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच में समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता पर सहमति बनी है। इससे भारतीय उत्पादों पर करों में कमी आएगी और कारोबार बढ़ेगा।

भारत-बांग्लादेश के बीच मंगलवार को हुई द्विपक्षीय बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन के रिश्तों को लेकर न सिर्फ भारत को आश्चर्य किया बल्कि स्पष्ट रूप से कहा कि उनका लक्ष्य अपने देश की प्रगति है तथा वह किसी द्विपक्षीय संबंधों को किसी तीसरे की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होने देंगी।

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- सिद्दीक कम्पन क पीएफआई के साथ करीबी संबंध, बड़ी साजिश का हिस्सा

नई दिल्ली, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक कम्पन के चरमपंथी संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ 'करीबी संबंध' और 'गहरे संबंध' थे।

राज्य सरकार ने लिखित जवाब में कहा, 'सामने आया कि सीएफआई के नेशनल सेक्रेटरी राउफ शरीफ ने उसे इस यात्रा के लिए वित्तीय सहायता दी थी। जांच में समाने आया कि कम्पन पत्रकार के रूप में इसलिए जा रहा था ताकि वह अंडर कवर रहे। यूपी सरकार ने कहा, कम्पन सहआरोपी सीएफआई के राउफ शरीफ के साथ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत धर्मिक कलह फैलाने और देश में आतंक फैलाने का प्रयास किया गया।'

राज्य सरकार ने पीएफआई और सीएफआई के साथ याचिकाकर्ता के लिंक को स्थापित करने के लिए व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया और जांच में पीएफआई/सीएफआई (कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई की छात्र शाखा) के साथ आतंकी फंडिंग/



योजना के साथ कम्पन के गहरे संबंध दिखाई दिए। राज्य सरकार ने कहा, 'याचिकाकर्ता के खिलाफ एक स्पष्ट प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया है, जो पीएफआई के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर, सांप्रदायिक तनाव फैलाने, दंगे और आतंक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेख लिख रहा है।'

इसमें आगे कहा गया है, 'भले ही चार्जशीट दायर कर दी गई हो, पूरे आतंकवादी सेल की जांच अभी भी जारी है, वास्तव में पीएफआई नेतृत्व, पी. कोया और कमल के.पी. को नोटिस दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। इस बात की पूरी संभावना है कि आरोपी

द्वारा और सबूत खोजे जा सकते हैं और उससे छेड़छाड़ की जा सकती है।'

इसने आगे दावा किया कि कम्पन के लैपटॉप और दिल्ली में उनके किराए के घर से बरामद दस्तावेज, यह स्थापित करते हैं कि वर्तमान पीएफआई नेतृत्व में मूल रूप से सिमी (स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया- एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित) के सदस्य शामिल थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कम्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई 9 सितंबर को करने वाली है।

बघेल सरकार करेगी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन, बच्चों से लेकर बुजुर्ग ले सकेंगे भाग

नई दिल्ली, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार एक साल पहले ही चुनावी मोड में आ गई है। प्रदेश में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने नई पहल की है। प्रदेश में इस साल से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसमें फैसला लिया गया कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कबड्डी, खो-खो से लेकर टेनिस बाल क्रिकेट जैसे खेल प्रतियोगिताएं होंगी, तो वहीं इस ओलंपिक में बच्चों से लेकर सौ साल के बुजुर्ग भी बतौर प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। खास बात यह कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में शामिल होने के लिए खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2022 में कबड्डी, खो-खो, गेड्डी, पिट्टल, वॉलीबॉल, हॉकी और टेनिस बाल क्रिकेट को शामिल किया गया है। इन खेलों के मुकाबले पुरुष

और महिला दोनों श्रेणियों में होंगे। वहीं ओलंपिक खेल का आयोजन चार स्तरों ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर होगा। राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन राजधानी रायपुर में होगा। इन खेलों के आयोजन में तकनीकी सहायता हेतु छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षक, राज्य और जिला खेल संघ के प्रतिनिधि एवं शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करेंगे। एथलीटों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बतौर खिलाड़ी करियर को बढ़ाने का यह सुनहरा मौका है।

प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं 146 ब्लॉक स्तर पर होने वाले खेल आयोजन के लिए अलग-अलग समितियां गठित की जाएंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों के संयोजक सरपंच होंगे और ब्लॉक स्तर पर गठित समितियों के संयोजक विकासखंड अधिकारी होंगे। खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के भोजन, आवागमन

एवं अन्य सुविधाओं के लिए ग्राम पंचायतों और विकासखंडों के लिए बजट उपलब्ध कराया जाएगा।

भूपेश बघेल ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद छत्तीसगढ़िया संस्कृति और ग्रामीण परंपरा को आगे बढ़ाने की विशेष पहल की है। मुख्यमंत्री बघेल खुद भी अनेक मौकों पर पारंपरिक खेलों में हाथ आजमाते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री का पारंपरिक खेलों से लगाव इस तरह से भी देखने को मिला है कि भेंट मुलाकात समेत उनके कार्यक्रम के दौरान वे बच्चों के बीच पहुंचकर धौंरा, कंचे, गुल्ली-डंडा, पिट्टल खेलने लगते हैं।

इसके अलावा कैबिनेट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति वर्ग के हित में तत्परता से कार्यवाही एवं उनसे संबंधित नीति विषयक मामलों में अनुशंसा के लिए अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है। इस परिषद के गठन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग की बेहतर और उनके जीवन स्तर में तेजी से सकारात्मक बदलाव लाना है तथा उन्हें शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।



इस परिषद के गठन से राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के हित में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सार्थक सलाह-मशविरा मिलने के साथ ही बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी। परिषद की अनुशंसा के आधार पर शासन-प्रशासन को अनुसूचित जाति वर्ग की बेहतर के लिए आवश्यक सुधार के फैसले लेने में मदद मिलेगी। परिषद में इस वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि सदस्य समाज की स्थिति में तेजी से सकारात्मक बदलाव लाना है तथा उन्हें शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषयक पर अनुशंसा के लिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद का गठन पूर्व में ही हो चुका है। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किए जाने प्रक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशोरूप शुरू कर दी गई है। इस परिषद में वर्ग विशेष की समस्या आवश्यकता पर विचार किया जाएगा। वहीं इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन में आसानी

राहुल को पाकिस्तान में करनी चाहिए 'कांग्रेस जोड़ो यात्रा', एकजुट है देश : हिमंत बिस्वा



गुवाहाटी, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि 1947 में कांग्रेस के तहत भारत का विभाजन हुआ था। अब कांग्रेस को 'भारत जोड़ो यात्रा' के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए। राहुल गांधी को यह यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए क्योंकि भारत एकजुट है।

सरमा की यह टिप्पणी तब आई है जब एक दिन पहले कांग्रेस ने उनपर और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए और सीबीआई को पत्र लिखकर आरोपों की जांच की मांग की। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को दिल्ली में सीबीआई को ज्ञापन सौंपा और जंतर-मंतर पर धरना दिया।

इसमें एआईसीसी प्रभारी जितेंद्र सिंह और असम इकाई के प्रमुख भूपेन कुमार बोरा सहित कई शीर्ष

नेताओं ने भाग लिया था।

एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने कहा था, 'असम में मेरे सहयोगियों ने असम के सीएम के खिलाफ सात विशिष्ट मामलों पर सीबीआई जांच की मांग की है। हिमंत बिस्वा सरमा को ग्रेट बीजेपी वॉशिंग मशीन का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन उनके खिलाफ सबूत हैं। क्या सीबीआई को अपना काम करने की अनुमति दी जाएगी।'

सीबीआई को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया, 'असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीबीआई, भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती है और सीबीआई द्वारा तत्काल जांच करने के लिए तुरंत कदम उठाने का अनुरोध करती है। सच्चाई का पता लगाना और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।'

यात्रा से 'भारत जोड़ो' और 'कांग्रेस जोड़ो' दोनों लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं : शशि थरूर

तिरुवनंतपुरम, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस की यात्रा पूरे देश में कांग्रेस से जुड़े लोगों तथा अन्य को एकजुट कर सकती है और इसलिए इससे भारत जोड़ो और कांग्रेस जोड़ो दोनों ही लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सात सितंबर अर्थात कल से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह यात्रा 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी और लगभग 150 दिनों की इस पदयात्रा में 3,570

किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। थरूर ने भारत जोड़ो यात्रा के एक दिन पहले न्यूज एजेंसी से एक साक्षात्कार में कहा इस यात्रा का मकसद यह संदेश देना भी है कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जो भारत को जोड़ कर रख सकती है और अगर जनता तक यह संदेश भली भांति पहुंच गया तो इससे पार्टी में भी फिर से जान आ जाएगी। थरूर के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि कई नेता कांग्रेस अध्यक्ष पद का



चुनाव लड़ेंगे जिससे निर्वाचकों को व्यापक विकल्प मिलेंगे। हालांकि थरूर ने खुद चुनाव लड़ने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी।

कुछ नहीं होने वाला, दिल्ली में दिन काट रहे नीतीश : सम्राट चौधरी

पटना, 06 सितम्बर (का.सं.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए दिल्ली में नेताओं के घर घर जाकर मिल रहे हैं। मुलाकातों के इस सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ वामपंथी, समाजवादी और जदए के नेताओं से मिले। मेदांता हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने इलाज करा रहे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव और वहां मौजूद अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। इधर, नीतीश कुमार के दिल्ली

दौरे पर बीजेपी के नेताओं की पेनी नजर है। बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार के हर कदम पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। इस बीच, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक की यात्रा कर लें, उससे कुछ होने जाने को नहीं है। बिहार की जनता ने उनकी विदाई का दिन और तारीख तय कर दिया है। अब कोई उनपर विश्वास नहीं करेगा। वे बार-बार पाला बदलते

रहे हैं। जनता यह भी समझ चुकी है कि नीतीश कुमार जिसके साथ नहीं जाने का संकल्प लेते हैं उसके साथ भी चले जाते हैं। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि नीतीश कुमार अपने शासनकाल के अंतिम दौर में हैं। इसी वजह से वे कभी राजगीर तो कभी दिल्ली में दिन काट रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने की हसरत पाल बैठे मुख्यमंत्री को उनके ही सहयोगियों से भाव नहीं मिल रहा है। यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी एकजुटता के नाम पर दिल्ली में बिहार का पैसा बर्बाद करने



के लिए 3 दिन तक डेरा डालने वाले मुख्यमंत्री की भारी फजीहत हो गई है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने नीतीश कुमार की गलतफहमी दूर कर दी है। इससे पहले सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जदयू ने नीतीश कुमार

को मिशन इम्पासिबल पर लगा दिया है। जिन नेताओं को वे एकजुट करने में पसीना बहा रहे हैं वे कभी साथ नहीं आ सकते। जेपी के समर्थक नीतीश कुमार कांग्रेस की सबसे नकारा पीढ़ी के आगे नतमस्तक हो गए।

सरकार ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की किस्त जारी की

नई दिल्ली, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवल्युशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी की। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। आयोग ने 2022-23 के लिए 14 राज्यों को 86,201 करोड़ रुपये के कुल पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की है।

अनुशंसित अनुदान व्यव विभाग द्वारा 12 समान मासिक किस्तों में जारी किया जाता है।

सितंबर के लिए छठी किस्त जारी होने के साथ ही 2022-23 में राज्यों को जारी अनुदान की कुल राशि 43,100.50 करोड़ रुपये हो गई है।

चालू वित्त वर्ष के लिए जिन राज्यों की सिफारिश की गई है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

मंत्री शर्मा ने श्रम

विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। बैठक की शुरुआत में श्रम सचिव सुश्री नम्रता थापा ने पिछले तीन वर्षों तक विभाग का दायित्व संभालने वाले मंत्री शेरपा के योगदान की सराहना की और नये सिरे से विभाग का दायित्व संभालने वाले मंत्री शर्मा का स्वागत किया। वहीं अपने संक्षिप्त वक्तव्य में मंत्री शर्मा ने कार्यक्रम में स्वागत हेतु धन्यवाद देते हुए श्रम विभाग के जारी कार्यों एवं योजनाओं को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी, कड़े परिश्रम, समयबद्धता को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी से पूरी गम्भीरता के साथ कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया। वहीं इस दौरान मंत्री एमएन शेरपा ने भी मंत्री शर्मा का स्वागत करते हुए अपने कार्यकाल में श्रम मंत्रालय द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आने वाले दिनों में भी श्रमिकों के कल्याण हेतु कदम उठाये जाने की उम्मीद जतायी। इसके पश्चात मंत्री शर्मा ने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ एक चर्चा सत्र में भी भाग लिया। बाद में मंत्री शर्मा ने श्रम विभाग के विभिन्न विभागों का दौरा भी किया।

खेलो इंडिया सेंटर

मामलों के विभाग द्वारा जारी विज्ञापित के अनुसार एडीसी (विकास) गायस पेगा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में खेला इंडिया सेंटर के जिला बॉक्सिंग कोच के तौर पर पूर्ण हांग सुब्बा और बैडमिंटन कोच के तौर पर नीम तेनज़िंग शेर्पा नियुक्त किये गये। वहीं खेल व युवा मामलों के जिला निदेशक द्वारा जिलास्तरीय खेलो इंडिया सेंटर पर संक्षिप्त रिपोर्ट पेश की गयी। इस दौरान एक चर्चा सत्र भी आयोजित हुआ।

सिक्किम का नाम

में भाग ले रहे खिलाड़ियों से अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सिक्किम का नाम रोशन करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग के नेतृत्व वाली सरकार में राज्य में खेलों को उच्च प्राथमिकता देते हुए हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने प्रतियोगिता के प्रथम चरण के विजेताओं में प्रमाणपत्र एवं मेडल का वितरण भी किया। प्रतियोगिता में सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कुबेर भंडारी, खेल विभाग के संयुक्त सचिव सीबी राई, सिक्किम स्टेट कराटे टू एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष भीम सुब्बा एवं अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे।

पशुपालन सचिव मिल्क

केवल अच्छी गुणवत्ता के दूध की मांग है। वहीं इस दौरान उन्होंने विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटियों की शिकायतें एवं मांगें भी सुनीं।

उल्लेखनीय है कि एक संगठित संस्था के तौर पर सिक्किम मिल्क यूनियन को दूध की गुणवत्ता पर खास ध्यान देना पड़ता है। राज्य के मिल्क यूनियन को आपूर्ति करने वाले वालों को देश में सर्वाधिक भुगतान किया जाता है। यूनियन द्वारा सभी डेयर कोऑपरेटिव को उनके द्वारा आपूर्ति किये गये दूध का हर महीने की 5 तारीख तक भुगतान कर दिया जाता है। वहीं मिल्क यूनियन के अधीन डेयरी किसानों को सरकारी की ओर से 8 रुपये प्रति लीटर की दर से सहायता राशि भी दी जाती है। यह देश में किसी भी राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि है।

60 बच्चों को

संगठन द्वारा बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों को देश के बाहर भी अपनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान एडीडीएसएसएस प्रतिनिधियों द्वारा पाकिम डीसी, एसपी एवं एसडीएम को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान एडीडीएसएसएस प्रशासक सुदीप बोम्बान, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं अन्य भी मौजूद रहे।

विपक्ष को एकजुट करना ही हमारा लक्ष्य : नीतीश

नई दिल्ली, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं। नीतीश कुमार ने मंगलवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली के समकक्ष अरविंद केजरीवाल से मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुलाकात की। कुमार की इस मुलाकात का उद्देश्य वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करना है।

दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) नेता संजय झा भी मौजूद थे।

केजरीवाल से पहले कुमार ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डॉ. राजा से भी उनके पार्टी कार्यालयों में मुलाकात की थी। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं और उनकी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है।

बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, हमने चर्चा की है कि अगर वाम



दलों, राज्यों में क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस समेत सभी दल एक साथ आते हैं, तो यह एक बड़ा राजनीतिक गठन होगा।

येचुरी ने कहा कि यह सकारात्मक संकेत है, जिससे देश में अच्छा राजनीतिक विकास होगा। कुमार का दोपहर में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटला से भी मिलने का कार्यक्रम है।

जदयू नेता सभी विपक्षी दलों को वर्ष 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का संयुक्त मुकाबला करने के लिए

एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका विशेष जोर समाजवादी पृष्ठभूमि की पार्टियों को एकसाथ लाने पर है।

पिछले महीने भाजपा से नाता तोड़ने वाले कुमार ने रविवार को कहा था कि उनका एकमात्र लक्ष्य भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष को एकजुट करना है।

कुमार ऐसे समय दिल्ली के दौरे पर आए हैं जब कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव के लिए वाम विपक्ष के प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार हो सकते हैं।

नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ एकीकृत मोर्चा बनाने पर विपक्षी नेताओं से बातचीत करने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे।

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ करीब एक घंटे तक बैठक की।

नई दिल्ली पहुंचने से पहले, नीतीश कुमार ने पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड्री देवी के आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात की। बैठक में उनके साथ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे।

दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, देशभर में 30 जगह छापेमारी

नई दिल्ली, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली और कुछ राज्यों में करीब 40 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा कुछ अन्य अधिकारी आरोपी हैं। इस नीति को हालांकि वापस ले लिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में करीब 38-40 स्थानों की तलाशी ली जा रही है और मामले में नामजद लोगों के खिलाफ भी छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया कि इनमें से कोई भी स्थान सिसोदिया (50) या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी से संबद्ध नहीं है। संघीय एजेंसी ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी का सजाान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत मामले में जांच शुरू की। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में सिसोदिया और 14 अन्य को नामजद किया है। सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया, आईएसएस (भारतीय प्रशासनिक अधिकारी) अधिकारी एवं दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा के आवास सहित सात राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 19 अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी।

सिसोदिया के पास दिल्ली का आबकारी विभाग तथा शिक्षा विभाग सहित कई विभाग हैं। ईडी पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में जांच कर रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी। उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया है।

सिसोदिया ने भी नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी। दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सूत्रों ने दावा किया कि

सिबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियमावली-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी।

रिपोर्ट में पाया गया था कि निविदा जारी करने के बाद शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर और घोर प्रक्रियात्मक चूक की गई।

अधिकारियों के राजकोष को नुकसान पहुंचाकर निविदाएं जारी की गईं और इसके बाद शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया।

सूत्रों ने दावा किया कि

सिबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियमावली-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी।

रिपोर्ट में पाया गया था कि निविदा जारी करने के बाद शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर और घोर प्रक्रियात्मक चूक की गई।

अधिकारियों के राजकोष को नुकसान पहुंचाकर निविदाएं जारी की गईं और इसके बाद शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया।

सूत्रों ने दावा किया कि



आबकारी विभाग ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के नाम पर लाइसेंसधारियों को निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144.36 करोड़ रुपये की छूट दी। उन्होंने बताया कि लाइसेंस के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये की बयाना प्रतीक राशि देनी पड़ेगी, जब वहाई अड्डा अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में विफल रहा था।

एक सूत्र ने कहा, यह दिल्ली आबकारी अधिनियम 2010 के नियम 48(11)(बी) का घोर

उल्लंघन था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि बोलीदाता को लाइसेंस प्रदान करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा, ऐसा न करने पर सरकार उसकी जमा राशि जब्त कर लेगी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई आबकारी नीति, 2021-22 को पिछले साल 17 नवंबर से लागू किया गया था और इसके तहत निजी बोलीदाताओं को शहरभर में 32 क्षेत्रों में 849 दुकानों के लिए खुदरा लाइसेंस जारी किए गए थे।

NAGALAND STATE LOTTERIES	
Draw Time: 01:00 PM	
DEAR TEESTA MORNING	
TUESDAY WEEKLY LOTTERY	
Draw No:93 DrawDate on:06/09/22	
1st Prize ₹ 1 Crore/- 81J 56831	
(Chitdang State Prize Set)	
Cons. Prize ₹1000/- 56831 (REMAINING ALL SERIALS)	2nd Prize ₹ 9000/-
03989 32382 37386 43334 43377 61370 70091 75609 85293 91248	3rd Prize ₹ 450/-
0757 2020 4340 4433 4662 4868 6456 6858 8664 9390	4th Prize ₹ 250/-
1121 1427 5061 6398 6580 6859 7936 8291 8605 8767	5th Prize ₹ 120/-
0140 0221 0451 0911 0983 0994 1164 1179 1277 1481	0113 0464 0563 0591 0612 0731 0846 1032 1269 1327
1357 1693 1879 1941 2028 2154 2252 2295 2306 2310	1293 1391 1392 1468 1622 1694 1789 1800 2175 2481
2329 2346 2523 2786 2797 2846 2851 2948 2989 3022	2522 2631 2664 2704 2707 2887 2929 2945 2958 3122
3068 3305 3356 3637 3850 4006 4130 4179 4190 4393	3271 3299 3327 3454 3969 4077 4182 4231 4249 4278
4460 4481 4492 4495 4553 4587 4687 4756 4872 5119	4297 4337 4491 4577 4609 4813 4891 4904 4912 5001
5129 5248 5271 5307 5722 5724 5757 5908 6151 6181	5077 5135 5282 5672 5768 5938 6144 6177 6505 6534
6334 6339 6454 6482 6490 6617 6619 6629 6650 6792	6537 6574 6618 6749 6790 6949 6971 7054 7532 7631
6824 6916 6990 7029 7141 7156 7287 7569 7753 7959	7668 7675 7712 7828 7909 7987 8012 8104 8169 8256
7961 8147 8244 8396 8481 8511 8526 8527 9090 9257	8395 8396 8672 8681 8956 9046 9258 9335 9358 9373
9297 9348 9547 9588 9764 9772 9777 9840 9983 9991	9381 9450 9474 9486 9550 9617 9703 9732 9828 9974
ISSUED BY : THE DIRECTOR	
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND	
For Results, Please Visit : www.Nagalandlotteries.com	
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE	

NAGALAND STATE LOTTERIES	
Draw Time: 08:00 PM	
DEAR PARROT EVENING	
TUESDAY WEEKLY LOTTERY	
Draw No:193 DrawDate on:06/09/22	
1st Prize ₹ 1 Crore/- 72K 68003	
(Chitdang State Prize Set)	
Cons. Prize ₹1000/- 68003 (REMAINING ALL SERIALS)	2nd Prize ₹ 9000/-
06651 15489 29939 32347 48813 52123 56865 58808 66175 69696	3rd Prize ₹ 450/-
0545 0977 3485 4192 5920 7237 7462 7677 9253 9286	4th Prize ₹ 250/-
1171 1203 1422 1860 2483 4154 4293 6390 8401 9767	5th Prize ₹ 120/-
0113 0464 0563 0591 0612 0731 0846 1032 1269 1327	0113 0464 0563 0591 0612 0731 0846 1032 1269 1327
1357 1391 1392 1468 1622 1694 1789 1800 2175 2481	1293 1391 1392 1468 1622 1694 1789 1800 2175 2481
2522 2631 2664 2704 2707 2887 2929 2945 2958 3122	2522 2631 2664 2704 2707 2887 2929 2945 2958 3122
3271 3299 3327 3454 3969 4077 4182 4231 4249 4278	3271 3299 3327 3454 3969 4077 4182 4231 4249 4278
4297 4337 4491 4577 4609 4813 4891 4904 4912 5001	4297 4337 4491 4577 4609 4813 4891 4904 4912 5001
5077 5135 5282 5672 5768 5938 6144 6177 6505 6534	5077 5135 5282 5672 5768 5938 6144 6177 6505 6534
6537 6574 6618 6749 6790 6949 6971 7054 7532 7631	6537 6574 6618 6749 6790 6949 6971 7054 7532 7631
7668 7675 7712 7828 7909 7987 8012 8104 8169 8256	7668 7675 7712 7828 7909 7987 8012 8104 8169 8256
8395 8396 8672 8681 8956 9046 9258 9335 9358 9373	8395 8396 8672 8681 8956 9046 9258 9335 9358 9373
9381 9450 9474 9486 9550 9617 9703 9732 9828 9974	9381 9450 9474 9486 9550 9617 9703 9732 9828 9974
ISSUED BY : THE DIRECTOR	
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND	
For Results, Please Visit : www.Nagalandlotteries.com	
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE	

NAGALAND STATE LOTTERIES	
Draw Time: 06:00 PM	
DEAR MOON TUESDAY	
WEEKLY LOTTERY	
Draw No:93 DrawDate on:06/09/22	
1st Prize ₹ 1 Crore/- 92J 76217	
(Chitdang State Prize Set)	
Cons. Prize ₹1000/- 76217 (REMAINING ALL SERIALS)	2nd Prize ₹ 9000/-
04952 21166 23943 24739 29891 57683 67271 78692 81193 99675	3rd Prize ₹ 450/-
0026 0773 0937 1140 2414 2825 4547 6036 7373 8578	4th Prize ₹ 250/-
0451 2056 2077 2859 4591 5056 7413 8649 8689 9843	5th Prize ₹ 120/-
0012 0235 0351 0422 0635 0659 0742 1101 1229 1272	0012 0235 0351 0422 0635 0659 0742 1101 1229 1272
1293 1326 1344 1566 1622 1648 1843 1910 2245 2472	1293 1326 1344 1566 1622 1648 1843 1910 2245 2472
2527 2683 2765 3204 3229 3240 3409 3484 3863 3932	2527 2683 2765 3204 3229 3240 3409 3484 3863 3932
4019 4153 4158 4252 4268 4271 4407 4420 4449 4503	4019 4153 4158 4252 4268 4271 4407 4420 4449 4503
4686 4687 4741 4802 4966 5082 5399 5543 5576 5679	4686 4687 4741 4802 4966 5082 5399 5543 5576 5679
5847 5949 5963 6099 6141 6160 6168 6262 6448 6569	5847 5949 5963 6099 6141 6160 6168 6262 6448 6569
6609 6626 6778 6824 6956 6987 7024 7106 7149 7154	6609 6626 6778 6824 6956 6987 7024 7106 7149 7154
7243 7266 7386 7623 7652 7716 7742 7744 7828 8067	7243 7266 7386 76

लिज ट्रस की परीक्षा शुरू

करीब दो महीने लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद ब्रिटेन की सत्तारूढ़ पार्टी ने लिज ट्रस के रूप में देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक शुरू में इस पद के प्रबल दावेदार के रूप में उभरे थे, लेकिन समय के साथ वह दौड़ में पीछे होते गए और आखिर में करीब 21 हजार वोटों के अंतर से लिज ट्रस जीत गई। इसके साथ ही तीन वर्षों का बोरिस जॉनसन का कार्यकाल औपचारिक तौर पर समाप्त हुआ, जो 2019 में उनकी असाधारण जीत के साथ जनता की बड़ी हुई उम्मीदों के बीच शुरू हुआ था, लेकिन अप्रिय स्कैंडलों और विवादों की याद छोड़ते हुए निराशाजनक ढंग से समाप्त हुआ।

बहरहाल, लिज ट्रस की नई पारी चुनौतियों के बीच शुरू हो रही है। उनके प्रधानमंत्री चुने जाने से चंद दिन पहले ही ब्रिटेन जो दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, खिसककर छठे नंबर पर आ गया। उसे पीछे छोड़ा है भारत ने, जो एक समय में उसका उपनिवेश हुआ करता था। इस मनोवैज्ञानिक और काफी हद तक सांकेतिक झटके को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें तो भी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कई तरह की चुनौतियों से घिरी है। यूक्रेन युद्ध के कारण देश असाधारण ऊर्जा संकट से गुजर रहा है।

लोगों के बढ़े हुए बिजली बिल एक बड़ा मुद्दा है, जो प्रधानमंत्री चयन की इस प्रक्रिया के दौरान भी छाया रहा। इस प्रक्रिया की एक खास बात यह भी कही जाएगी कि इस दौरान वित्तीय नीति को लेकर भी अच्छी बहस हुई। जहां ऋषि सुनक का कहना था कि टैक्स कटौती जैसे पॉप्युलिस्ट कदम से देश की वित्तीय स्थिति और खराब होगी वहीं, लिज ट्रस का कहना था कि मौजूदा हालात में टैक्स कटौती के जरिए लोगों को राहत देना अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद अपने पहले भाषण में भी लिज ट्रस ने इस वादे को दोहराते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वह देशवासियों से किए सारे वादे पूरे कर पाएंगी। उनके पास वक्त सिर्फ दो साल का है। लेकिन उन्हें वादे वे सारे पूरे करने हैं जो पिछले चुनावों के दौरान उनकी पार्टी ने किए थे। तभी वह 2024 में पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लिए एक पूरा कार्यकाल मांगने की स्थिति में होंगी।

फिलहाल सबसे पहले उन्हें अपनी एक भरोसेमंद और काबिल टीम बनाकर मंत्रिमंडल का गठन करना है और बुरी तरह बंटी हुई दिख रही कंजर्वेटिव पार्टी के सभी धड़ों को साथ लाना है। जाहिर है, कम समय में उन्हें बेहद कठिन लक्ष्य पूरे करने हैं, लेकिन इतिहास भी ऐसी ही स्थितियों में बनते हैं। लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। तरीसा मे और मार्गरेट थैचर से उनकी तुलना स्वाभाविक है, लेकिन इन खींची हुई लकीरों को वह कितना बड़ा या छोटा साबित करती हैं यह भविष्य में उनके प्रदर्शन से तय होगा।

संवादकीय पृष्ठ

हल्ला बोल रैली : साफगोई से बनेगी बात

क्वण प्रताप सिंह
रविवार को कांग्रेस द्वारा राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में की गई हल्ला बोल रैली को नरेन्द्र मोदी सरकार की रीति-नीति के खिलाफ उसकी अब तक की रैलियों से इस अर्थ में अलग से रेखांकित किया जा सकता है कि वह महंगाई व बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हल्ला बोलने के अपने पूर्व घोषित एजेंडे तक ही सीमित नहीं रही।
उसे संबोधित करने वाले ज्यादातर नेताओं ने देश की इनसे इतर कई ऐसी चिंताओं को भी स्वर दिया जो उसके निवासियों को कहीं ज्यादा मथ रही है।
इनमें सबसे बड़ी चिंता निरसंदेह लोकतंत्र के भविष्य से ही जुड़ी हुई है, जो विभिन्न संवैधानिक व विधिक संस्थाओं के सत्ताप्रायोजित क्षरण के चलते लगातार अंधेरा व काला होता जा रहा है। राहुल गांधी ने रैली में इसकी क्रोनोलाजी कुछ इस तरह समझाई: डरे हुए सत्ताधीश देश में भविष्य, महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े डरों को लगातार बढ़ा कर रहे हैं। इन डर से नफरत और गुस्से का जन्म हो रहा है, जिससे लोग बंट रहे हैं और देश कमजोर हो रहा है। उसके यों कमजोर होने का सारा दर्द आम आदमी को व सारा लाभ महज दो उद्योगपतियों को मिल रहा है। इन उद्योगपतियों व इनके द्वारा नियंत्रित मीडिया की बदौलत ही मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और अपने विरुद्ध कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने विपक्ष की आवाज तो दबा ही दी है, प्रायः सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को शक्तिहीन करके रख दिया है। इसलिए अब विपक्ष के पास जनता के पास जाने और उससे सीधा संवाद करने के अलावा कोई

रास्ता नहीं बचा है।
आगे उन्होंने कहा कि अब भारत जोड़ो यात्रा में हम सीधे जनता के ही पास जाएंगे, उसकी आवाजें जोड़ेंगे और उसकी शक्ति से राजा को सुनने को मजबूर करेंगे। यानी इसका ज्ञान उन्हें बहुत देर से प्राप्त हुआ है और जहां तक जनता के पास जाने का ही रास्ता बचने की बात है, तो यह स्थिति तो 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बने के बाद से ही बनी हुई है और 2019 के लोक सभा चुनाव में जनता के पास जाकर भी कांग्रेस उसे नहीं बदल पाई, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह क्रोनोलाजी गलत है या कि उसे सामने लाने में इतनी देर हो चुकी है कि वक्त हाथ से निकल गया है।
वह निकल गया होता तो सत्ता पक्ष को इस हल्ला बोल रैली से इतना डर न सताता कि वह अपने समर्थक पत्रकारों से एडवांस में ऐसी अफवाह उड़ाने को करे कि रैली को लेकर सकारात्मक ट्वीट करने वाले पत्रकारों को कांग्रेस की ओर से पैसे दिए गए हैं। हां, कह सकते हैं कि जो समय उनके व उनकी पार्टी के सामने बरबस आ खड़ा हुआ है, उसका उन्होंने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो कौन जाने लौटकर वापस चले जाने के बाद वापस आने में वह कितनी देर कर दे। यहाँ ठीक से इस्तेमाल को ठीक से समझ लेना चाहिए। यह ठीक से इस्तेमाल सिर्फ रैलियों में क्रोनोलाजी समझाने या भारत जोड़ो जैसी यात्राएं निकालने से ही संभव नहीं होगा। हां, जैसे राहुल ने पहली बार स्पष्ट क्रोनोलाजी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को निर्णायक संघर्ष का रास्ता दिखाने की कोशिश की है, वैसे ही पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों को भी स्पष्ट व पारदर्शी रूप देकर पार्टी के

भीतर उन पर आम सहमति बनानी होगी।

हताशा व निराशा के शिकार कार्यकर्ता इसके बगैर शायद ही उनकी रक्षा के प्रति खुद को सच्चे मन से समर्पित कर पाएँ। इस बात को इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब राहुल कहते हैं कि मोदी सरकार की नीतियों का सारा फायदा दो उद्योगपतियों को ही मिल रहा है तो उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि कांग्रेस या उसके गठबंधन द्वारा शासित राज्यों की सरकारों की नीतियां उन उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाती न दिखें। याद कीजिए, 2019 में पांच अगस्त को मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया तो भी किस तरह कांग्रेस कोई लाइन ले रही थी और उसके अनेक नेता कुछ और। कई नेताओं ने तो सरकार के कदम के समर्थन से भी गुरेज नहीं किया था। कहने का आशय यह कि अगर सत्ताधीशों की कथित विचारधारा खतरनाक व नुकसानदेह होने के बावजूद लोगों को सम्मोहित या उन पर इमोशनल अत्याचार करती है, जो वह करती ही है तो अपने लोगों को उस अत्याचार के पार ले जाने के उपाय किए बिना उससे लड़ाई में जीत नहीं हासिल की जा सकती। ऐसे सैनिकों के भरोसे तो कतई नहीं जो युद्ध के बीच खुद ऐसे अत्याचार के शिकार हो जाते हों। शायद इसी के मद्देनजर पिछले दिनों राहुल ने कहा था कि कांग्रेस के ऐसे नेता या कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपा से वैचारिक संघर्ष में उतरते हुए डरते हैं, छोड़कर जा सकते हैं और जो पहले से ऐसे संघर्ष में मुंबितला हैं या उसमें योगदान करना चाहते हैं, वे कांग्रेस के बाहर भी हैं तो वह वही अपनी ही तरह उनका स्वागत

करेंगे।

तिस पर, नतीजा कुछ भी हो, इन विकल्पों को आजमाने के सिवाय उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। क्योंकि अगर इस बार भूतपूर्व कर्हें या भावी अध्यक्ष के तौर पर वे अरसे से फूटग्रस्त कांग्रेस और उसके नेताओं व कार्यकर्ताओं को इसका अहसास नहीं करा पाए कि इस वक्त वे मजबूती से खड़े नहीं हुए तो कांग्रेस को आगे अपना अस्तित्व बचाने की जानें कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो देश भविष्य व इतिहास उन्हें माफ नहीं करने वाले। आखिरकार, जैसा कि पिछले दिनों एक प्रेक्षक ने कहा भी कि कांग्रेस भले गांधी परिवार या राहुल के पास है, वह देश की धरोहर है। सवाल है कि इस धरोहर की रक्षा के लिए वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से लड़ाई कैसे जीतेंगे, जब दुर्दिन में उन्हें छोड़कर गए योद्धा ही उनसे बारंबार युद्धम देह की मांग करते रहेंगे? इन योद्धाओं की मंशा को यों समझ सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने जम्मू-कश्मीर में अपनी रैली का वही दिन चुना, जो कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी हल्ला बोल रैली के लिए तय कर रखा था।

ऐसे में यह सवाल तो पूछा ही जाएगा कि क्या इसके बावजूद कांग्रेस जी-23 के गलाम नबी की राह पर जाने को आतुर अपने नेताओं का कोई इलाज ढूंढ पाई है? और जवाब इसलिए जरूरी है कि आंक सनापति कोई भी लड़ाई शुरू करने से पहले अपने अर्धों-शस्त्रों व सेनाओं को ठीक से सहेज लेते हैं-उनकी निष्ठा को भी। वरना अतीत गवाह है कि दुश्मन से हाथी युद्धविरत होकर लौटने लगते हैं तो अपनी ही सेना को कुचल डालते हैं।

आर्थिक प्रभुत्व की ओर : जीडीपी की विकास दर की निरंतर बनी रहे, तब आराम से आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत

अजय बग्गा
वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल-जून की तिमाही में देश की सकल घरेलू विकास (जीडीपी) दर 13.5 फीसदी हो गई, जो पिछली चार तिमाहियों में सबसे तेज है। विकास दर में यह तेज वृद्धि कृषि एवं विनिर्माण में सुधार तथा सेवा क्षेत्र के लगभग पूरी तरह से खुल जाने के कारण हुई है। हालांकि, यह वृद्धि अब भी रिजर्व बैंक के हालिया पूर्वानुमान (16.2 फीसदी) से कम है। 151 अर्थशास्त्रियों वाले रॉयटर्स सर्वेक्षण में भी अपने यहां पहली तिमाही में 15.2 फीसदी सालाना विकास दर की भविष्यवाणी की गई थी।
इसलिए 13.5 फीसदी का आंकड़ा भले मजबूत दिख रहा हो, लेकिन रिजर्व बैंक एवं बाजार की उम्मीदों से कम है। पिछले साल इसी अवधि में भारत की जीडीपी में 20.1 फीसदी की वृद्धि हुई थी। यह काफी हद तक कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण कम आधार रखे जाने के कारण था। इसके चलते अप्रैल-जून 2020 में जीडीपी में -23.8 फीसदी की बहुत तेज गिरावट देखी गई। इस संख्या को संदर्भ में रखने के लिए, आइए, कोविड पूर्व जीडीपी की तुलना जीडीपी पर कोविड के तीन वर्षों के प्रभाव से करते हैं।
अप्रैल से जून, 2018 के दौरान जीडीपी 33.82 लाख करोड़ रुपये थी। यह अप्रैल से जून, 2019 में बढ़कर 35.49 लाख करोड़ रुपये हो गई। जैसे ही कोविड लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, अप्रैल से जून, 2020 के दौरान जीडीपी तेजी से गिरकर 27.04 लाख करोड़ रुपये रह गई। अप्रैल से जून, 2021 में जीडीपी 32.46

लाख करोड़ रुपये थी। यह कोविड लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत था। हालांकि, इस अवधि के दौरान महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर थी और इसका आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
इस वर्ष अप्रैल से जून तक जीडीपी 36.85 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। हम जिस 13.5 फीसदी की बात कर रहे हैं, यह वही है। यदि हम वर्ष 2018 से इसकी तुलना करें, तो हमने चार वर्षों में कुल 8.9 फीसदी वृद्धि देखी है। यदि 2019 से तुलना करें, तो हमने तीन वर्षों में कुल 3.8 फीसदी की वृद्धि देखी है। तीन वर्षों के बाद यह पहली बार है, जब अर्थव्यवस्था कोविड लॉकडाउन के झटके से उबरी है। कुल मिलाकर, 2019-2022 की तुलना में 3.8 फीसदी वृद्धि के साथ, हमने कोविड के कारण अर्थव्यवस्था में तीन साल की वृद्धि खो दी है।
अगर हम इन वर्षों के उतार-चढ़ाव को नजर अंदाज करें और 2019 से 2022 की तुलना करें, तो यह पिछले तीन वर्षों में 1.2 फीसदी सालाना से कम की वृद्धि में तब्दील हो जाता है। यह 1.2 फीसदी की वृद्धि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में गरीबी घटाने और कल्याणकारी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोविड महामारी का प्रभाव स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा रहा है। केंद्र सरकार ने व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) बढ़ाने के लिए कई प्रशासनीय पहल की हैं। इससे विनिर्माण एवं निर्यात क्षेत्र में तेजी आई है।
आत्मनिर्भर भारत, मुद्रा ऋण, मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड जैसी क्षेत्रवार लक्षित उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं और रक्षा एवं उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन जैसी पहलों ने भविष्य के लिए एक मजबूत विकास मंच तैयार किया है। कृषि के मोर्चे पर भी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मुफ्त खाद्यान्न सुरक्षा तथा उच्च उर्वरक व खाद्य सस्ती के साथ-साथ उच्च एमएसपी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिये क्षेत्रीय विकास में मदद मिली है।
राजस्व के मोर्चे पर, जीएसटी और प्रत्यक्ष कर-दोनों ने बेहतर अनुपालन, कम रिसाव और अंतर्निहित अर्थव्यवस्था में सुधार के आधार पर अच्छी वृद्धि दिखाई है। प्रत्यक्ष कर ने, जिसमें व्यक्तिगत कर के साथ कॉर्पोरेट कर भी शामिल हैं, मौजूदा वित्त वर्ष में तेज वृद्धि दिखाई है। सरकार द्वारा इस वर्ष अपने कर संग्रह लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखें, तो चीन की सुस्ती, यूरोप में आसन्न मंदी की आशंका और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सुस्ती भी भविष्य में भारत की जीडीपी को प्रभावित करने वाली है।
पिछले पांच महीनों में दुनिया भर के 65 से अधिक केंद्रीय बैंकों द्वारा 90 से अधिक बार ब्याज दरों में 0.5 फीसदी से अधिक की वृद्धि की गई है। मौद्रिक तंगी, बढ़ती मुद्रास्फीति, मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण अन्य मुद्राओं में गिरावट और धू-राजनीतिक जोखिमों ने वैश्विक विकास को प्रभावित किया है। भारत में, घरेलू मांग दूसरी तिमाही में एक प्रमुख चालक थी। कोविड से निजी खपत में आई गिरावट में सुधार हुआ है। सरकारी

नीतीश को केंद्र से झटका, मनरेगा में बिहार का डिमांड 12 करोड़ वर्कडे था, मिला 2.5 करोड़

पटना, 06 सितम्बर (का.सं.)। बिहार की नीतीश सरकार को मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार से झटका लगा है। मनरेगा के अंतर्गत नीतीश सरकार ने केंद्र से 12 करोड़ वर्कडे (मानव दिवस) की मांग की थी। मगर केंद्र सरकार से अभी बाई करोड़ की ही मंजूरी दी गई है। हालांकि, केंद्र ने आश्वासन दिया है कि अगले दो महीने के भीतर और भी अतिरिक्त वर्कडे की मंजूरी दी जाएगी। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार को 15 करोड़ मानव दिवस की सहमति दी गई थी। अगस्त के पहले सप्ताह में ही 14 लाख से अधिक दिनों का काम मजदूरों को दे दिया गया था। इसको देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने अतिरिक्त 12 करोड़ वर्कडे की मांग की थी। ताकि, 15 करोड़ का लक्ष्य पूरा होने के बाद भी राज्य में मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलने में कोई परेशानी न हो। नीतीश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शुरूआत में ही 25 करोड़ वर्कडे का प्रस्ताव दिया था, पर 15 करोड़ की ही स्वीकृति मिली। तब, केंद्र सरकार ने यह कहा था कि 15 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करें, बाद में इसे बढ़ा दिया जाएगा। पूर्व के सालों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20 करोड़ वर्कडे की स्वीकृति केंद्र सरकार ने बिहार को दी थी। इसके विरुद्ध पूरे साल में 18 करोड़ 20 लाख दिन का काम मजदूरों को दिया गया। वहीं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 22 करोड़ 79 लाख मानव दिवस बिहार में सृजित किए गए थे।

सही दिशा में बढ़ रहे हैं कदम

नितिन प्रधान
दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी नई पहचान बनाई है।
आकार के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यही नहीं कोविड महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था की सेहत में अब सुधार दिख रहा है।
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ने पिछले साल के मुकाबले 13.5 फीसद की वृद्धि दर्ज की है। हालांकि अर्थव्यवस्था की पहली तिमाही की यह रफ्तार भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन 16.2 से कम रही है। बावजूद इसके इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचा था उससे उबरने की सही दिशा पकड़ ली है। अलबत्ता, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि रिजर्व बैंक ने इस अवधि के लिए 16.2 फीसद की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। यानी अभी भी अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ है जो उसके स्वाभाविक विकास को बाधित कर रहा है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पूर्व हमें बीते तीन साल के कुछ आंकड़ों पर नजर डालनी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर को समझने में आसानी हो।
कोविड से ऐन पहले के वित्त वर्ष यानी 2019-20 की पहली तिमाही में जीडीपी का आकार 35.49 लाख करोड़ रूपये का था। बावजूद इसके इस वित्त वर्ष में जीडीपी का आकार 145.69 लाख करोड़ रूपये तक ही पहुंच पाया। इसलिए वित्त वर्ष 2018-19 के मुकाबले आर्थिक विकास दर या जीडीपी दर मात्र चार फीसद पर ही सिमट गई। अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 से और आगे बढ़ने की आस बंधी थी। लेकिन मार्च 2020 में कोविड के चलते लॉकडाउन की घोषणा हो गई और देश भर में आर्थिक गतिविधियां ठप हो गईं। नतीजा वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी का आकार घटकर 27.03 लाख करोड़ पर आ गया। विकास दर में लगभग 24 फीसद की गिरावट दर्ज की गई।
अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में स्थितियां सुधरी और जीडीपी का आकार 2021-22 में 20.1 फीसद बढ़कर 32.46 लाख करोड़ रुपये हो गया, लेकिन अभी भी कोविड पूर्व की पहली तिमाही के 35.49 लाख करोड़ रूपये से कुछ कम ही था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही ने इस बाधा को पार किया है और वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के आंकड़े को पार कर जीडीपी का आकार 36.85 लाख करोड़ रूपये हुआ है। यानी यदि कोविड की अवधि को निकाल दिया जाए तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अभी हम लगभग 2019 के स्तर पर ही खड़े हैं। आर्थिक मोर्चे पर अब हमें लगभग वहीं से शुरुआत करनी है जहां दो साल पहले हम पीछे छूट गए थे। अब बात करते हैं उन परेशानियों की जो अभी भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बाधित कर रही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अड़चन है महंगाई। हम सभी ने देखा है कि रिजर्व बैंक अब तक तीन बार रेपो रेट की दरों में वृद्धि कर चुका है, लेकिन उसका असर महंगाई पर अभी दिखा नहीं है।
रिजर्व बैंक के मुताबिक दरों में बदलाव के उसके निर्णयों का असर जमीन पर दिखने में आठ से नौ महीने का वक्त लगता है। यानी दो-तीन महीने अभी और इंतजार करना होगा। महंगाई का सर्वाधिक असर इस बार देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों की महंगाई की दर शहरों के मुकाबले ऊपर बनी हुई है। इस बार मानसून में देरी के चलते धान की बुआई भी प्रभावित हुई। इसका असर पैदावार पर भी होगा। मनरेगा में भी रोजगार की तेज मांग देखने को मिली है जो यह दर्शाती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था दबाव में है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत में ग्रामीण सेक्टर का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। पहली तिमाही में व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्प्यूटेशन आदि क्षेत्र की सेवाओं में 16.3 फीसद की वृद्धि दर दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी यह कोविड पूर्व 2019-20 की पहली तिमाही के 21.6 फीसद की वृद्धि दर से काफी पीछे है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में इस क्षेत्र को अभी आगे आना होगा।
वहीं निर्यात के मोर्चे पर अभी भी दिक्कत है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ने नहीं दे रही है। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र अभी भी पटरी पर नहीं आ पाया है। पहली तिमाही में मैन्यूफैक्चरिंग की वृद्धि दर मात्र 8.6 फीसद रही है, जबकि अनुमान इससे अधिक का था, लेकिन कृषि विकास दर अनुमान से अधिक 4.5 फीसद रही है। दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था का यह प्रदर्शन उसाहवर्धक है।
हालांकि महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े अभी भी चिंता का सबब बने हुए हैं। इसलिए नीति निर्माताओं की परीक्षा का भी यही सही वक्त है। कोविड महामारी के पूर्व की आर्थिक स्थिति को तो हमने पा लिया है। अब यहां से किस रफ्तार से आगे जाते हैं यह सरकार की नीतियों पर ही निर्भर करेगा। रिजर्व बैंक का अनुमान चालू वित्त वर्ष के लिए 7.3 फीसद की आर्थिक विकास दर का है, जबकि आइएमएफ ने इसी सप्ताह अपना अनुमान घटकर 7.4 फीसद की विकास दर दिया है।



ये हैं जेईई मेन परीक्षा फ्रैक करने के लिए जरूरी टिप्स

जेईई मेन एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है। इस परीक्षा का पहला सेशन फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाखों उम्मीदवार अपनी क्वालिफिकेशन को आज़माएंगे। देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली इस परीक्षा को देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक माना जाता है। अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर हम जेईई मेंस की प्रिपेरेशन प्लानिंग के बारे में पूरी जानकारी और टिप्स देंगे।

सिलेबस को समझ कर बनाएं प्लान

जेईई मेन की तैयारी के लिए छात्रों को प्रभावी प्लान बनाने की जरूरत पड़ेगी और इसमें मदद करेगा परीक्षा का सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस को समझे और इसके आसान और कठिन विषयों को ध्यान में रखकर अपनी प्रिपेरेशन प्लानिंग बनाएं। अपनी क्षमता और स्पीड के आधार पर, तीनों विषयों को शामिल करते हुए एक डेली प्रिपेरेशन प्लान बनाएं। इसका नियमित रूप से पालन भी करें।

बेहतर टाइम टेबल बनाएं

इस परीक्षा की तैयारी के लिए सही टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल को अपने परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाएं। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को 90 प्रश्नों में से 75 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक पेपर की अवधि 3 घंटे है। प्रत्येक विषय में 20 एमसीक्यू और 10 न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एमसीक्यू के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। वहीं, न्यूमेरिकल प्रश्नों में सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और इस खंड में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है।

मौजूदा टॉपिक को पूरा करें

इस परीक्षा के पहले अटेंट के लिए अब दो माह से कम समय बचा है। इसलिए तैयारी में आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि इस परीक्षा के प्रमुख टॉपिक को आप पूरा कर लें। उसके बाद दूसरे टॉपिक को शुरू करें। यह तरीका आगे चलकर आपके लिए महत्वपूर्ण पहलू साबित होगा, क्योंकि जेईई मेन की तैयारी के अंतिम चरण के दौरान, उम्मीदवारों को अधिक जोर नहीं लगाना पड़ेगा।

प्लैश कार्ड तैयार करें

इस परीक्षा की तैयारी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। प्लैशकार्ड और शॉर्ट नोट्स तैयार करने का उद्देश्य मुख्य परीक्षा के आयोजन में जब एक सप्ताह का समय बचा हो, उस समय अधिक से अधिक समय को बचाकर इनसे तैयारी कर सकें। इनसे उम्मीदवार जल्दी से इन शॉर्ट नोट्स और प्लैश नोट्स के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहरा सकेंगे।

सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करें

जेईई मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए लगातार सैंपल पेपर और प्रश्न पत्रों को हल करें। जेईई मेन प्रश्न पत्र को हल करने का उद्देश्य उम्मीदवारों को उनकी तैयारी के स्तर को जानने में सक्षम बनाना है। इससे, उम्मीदवार यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि वे हर विषय में प्रत्येक प्रश्न को हल करने में कितना समय ले रहे हैं। साथ ही क्या वे अपने समय का उचित प्रबंधन कर पा रहे हैं या नहीं, यह समझ भी उनमें आएगी। जितना अधिक वे प्रश्नों को हल करेंगे, उन्हीं पता चल जाएगा कि वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें उन्हें अधिक काम करना होगा ताकि परीक्षा के दिन कोई कठिनाई न आए। वे अपनी कमियों को दूर कर अपनी प्रदर्शन में सुधार कर सकेंगे।

लगातार मॉक टेस्ट दें

अब सभी परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट बेहद जरूरी हो गया है। यह हमें परीक्षा से पहले असफल परीक्षा का एहसास कराता है। अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट जरूर देने की कोशिश करें। इससे जेईई मेंस प्रवेश परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को किसी तरह के प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ेगा।

रिवीजन जरूर करें

सभी परीक्षा के लिए रिवीजन बहुत ही जरूरी है। इसके बिना परीक्षा को फ्रैक नहीं कर सकते। इसलिए, उम्मीदवारों को समय रहते जो कुछ पढ़ा है उसे अच्छी तरह से दोहरा लेना चाहिए। इससे टॉपिक को याद करने में काफी मदद मिलेगी। आप जो भी टॉपिक पढ़े उसका हर सप्ताह रिवीजन भी करें। इससे आपको याद करते में मदद मिलेगी।



डेंटल हाइजीनिस्ट बनकर संवारे अपना करियर

डेंटल हाइजीनिस्ट एक दंत पेशेवर है जो मौखिक स्वास्थ्य में माहिर है। इनका मुख्य काम आमतौर पर मौखिक स्वच्छता और देखभाल में तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। दंत चिकित्सक और डेंटल हाइजीनिस्ट मरीजों की मौखिक स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। शरीर के अन्य भागों की तरह ही दांत भी मनुष्य के शरीर का एक अहम हिस्सा हैं। आमतौर पर औरल हेल्थ का ख्याल रखना बेहद ही जरूरी माना जाता है और लोग इसका ख्याल रखते भी हैं। हालांकि दांतों व औरल हेल्थ से संबंधित कई बार लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसे में एक पेशेवर की जरूरत पड़ती है। जैसे जठ औरल हेल्थ को लेकर डॉक्टर का ख्याल आता है तो हम सभी डेंटल के पास जाना पसंद करते हैं। लेकिन अब, दंत चिकित्सा तेजी से बढ़ रही है, कई अवसरों और चुनौतियों का निर्माण कर रही है। दंत चिकित्सकों के रूप में मुख्य करियर के अलावा, दंत चिकित्सा सहायक, डेंटल हाइजीन के क्षेत्र में भी आप करियर के अवसर तलाश सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि डेंटल हाइजीनिस्ट बनकर आप अपना करियर कैसे संवार सकते हैं—

क्या होता है काम

करियर एक्सपर्ट बताते हैं कि डेंटल हाइजीनिस्ट एक दंत पेशेवर है जो मौखिक स्वास्थ्य में माहिर है। इनका मुख्य काम आमतौर पर मौखिक स्वच्छता और देखभाल में तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। दंत चिकित्सक और डेंटल हाइजीनिस्ट मरीजों की मौखिक स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट अमूमन डेंटल के मरीजों के दांतों की देखभाल करने और अच्छे मौखिक स्वास्थ्य को

डेंटल हाइजीनिस्ट बनकर संवारे अपना करियर

मंटेन रखने में रोगियों को शिक्षित करने में सहायता करते हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट के कुछ अधिक विशिष्ट कर्तव्यों में दांतों से टार्टर और प्लाक को हटाना, दांतों की सुरक्षा के लिए फ्लोराइड या सीलेंट लगाना, एक्स-रे लेना और उचित मौखिक स्वच्छता पर मरीजों को शिक्षित करना शामिल है। हाइजीनिस्ट मरीजों को अपने दांतों की देखभाल के बारे में बात करने में समय बिताते हैं। वे लोगों को उन प्रभावों के बारे में शिक्षित करते हैं जो उनके आहार और जीवन शैली का उनके दांतों पर प्रभाव डालते हैं। साथ ही वे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए तकनीकों और आदतों के बारे में बताते हैं।

शैक्षिक योग्यता

डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स को कई डेंटल कॉलेजों में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में पेश किया जाता है। जो छात्र डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं, उन्हें 12वीं की परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषय में पास करना अनिवार्य है।

व्यक्तिगत योग्यता

करियर एक्सपर्ट के अनुसार, डेंटल हाइजीनिस्ट की आंखों की रोशनी, सुनने और संवार कोशल अच्छा होना चाहिए। किसी भी अन्य चिकित्सा क्षेत्र के साथ, उन्हें दूसरों

की मदद करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, और दंत चिकित्सकों के निर्देशों का बारीकी से पालन करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा, अच्छा पारस्परिक कौशल, धैर्य, परिश्रम और उच्च स्तर की सटीकता एक अच्छा हाइजीनिस्ट होने के लिए आवश्यक कौशल हैं। एक टीम के रूप में काम करने की क्षमता भी इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

संभावनाएं ही संभावनाएं दंत चिकित्सा के क्षेत्र में बतौर डेंटल हाइजीनिस्ट बनकर भी आप एक अच्छा करियर देख सकते हैं। एक डेंटल हाइजीनिस्ट अस्पताल से लेकर कम्युनिटी डेंटल सर्विस के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा वे पीरियोडॉन्टिक्स या बाल चिकित्सा दंत चिकित्सा में भी काम कर सकते हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटल हॉस्पिटल, आर्म्ड फोर्स, पब्लिक हेल्थ अंक्टर व प्राइवेट रूप से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।

आमदनी

डेंटल हाइजीनिस्ट की आमदनी उनकी शिक्षा, अनुभव व स्थान के आधार पर भिन्न होती है। एक डेंटल हाइजीनिस्ट की आमदनी घंटे, दिन, सैलरी या कमिशन बेस पर हो सकती है। हालांकि इस क्षेत्र में एक फ्रेशर प्रति माह आठ से दस हजार रूपए वेतन प्राप्त कर सकता है।

प्रमुख संस्थान

- भारत इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली
- भारत यूनिवर्सिटी, चेन्नई
- जया पैरामेडिकल कॉलेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हरियाणा
- लक्ष्मी बाई इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस एंड हॉस्पिटल, पटियाला



कृषि का अध्ययन करने के बाद एक सफल उद्यमी कैसे बनें

उद्यमिता और कृषि बिलकुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कृषि एक उद्योग है, जो दुनिया भर में है और धरती की पूरी आबादी को प्रभावित करता है। और यह सही है कि कृषि उद्यमी की हमेशा जरूरत रहेगी। उद्यमिता आजकल हर जगह पाई जा सकती है। हर पेशे में एक उद्यमी क्षेत्र होता है। उस विशेष क्षेत्र में कृषि निश्चित रूप से बहुत अहम भूमिका निभाता है। उद्यमिता और कृषि बिलकुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कृषि एक उद्योग है, जो दुनिया भर में है और धरती की पूरी आबादी को प्रभावित करता है। और यह सही है कि कृषि उद्यमी की हमेशा जरूरत रहेगी।

उद्यमिता क्षेत्र के किसान आजकल अपने खेतों को व्यवसाय मानते हैं और वे उन्हें ऐसा ही मानेंगे। वे जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, वे नई और इनोवेटिव तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे और सामान्य तौर पर वे अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सब कुछ करेंगे जो उन विचारों के साथ आएंगे जो उनके लाभ को अधिकतम करेंगे, उनके प्रयास को कम करेंगे और उनके व्यवसाय को बढ़ाएंगे। आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए उद्यमियों की भूमिका को मान्यता देते हुए विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर में कई पाठ्य कार्यक्रमों ने छात्रों के उद्यमिता कौशल को विकसित करने के लिए एक विषय के रूप में उद्यमिता को शामिल किया है। हालांकि, मौजूदा समय में नौकरियों को भरने के लिए कॉलेज में इस विषय का अध्ययन करने वाले पर्याप्त छात्र नहीं हैं। और इसके परिणामस्वरूप सफल कृषि व्यवसाय चलाने के अनुभव वाले कम लोग ही होंगे।

कृषि-उद्यमी बनने के लिए जरूरी कदम

प्रक्रिया का पहला चरण— यदि उद्यमिता की अवधारणा के साथ खुद को परिचित करना है तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि उद्यमशीलता क्या है और यह आपके खेत को कैसे लाभ पहुंचा सकती है। दूसरा कदम— कृषि की दुनिया के सभी नए नए विचारों के बारे में सीखना है। नई सामग्रियों और उर्वरकों से लेकर नई मशीनों और प्रौद्योगिकियों तक। इससे आपको अपने खेत को एक वास्तविक बड़े व्यवसाय के रूप में कल्पना करने में और उन सभी छोटी छोटी चीजों को व्यवस्थित करने में, जो आपको याद आ रही हैं, काफी मदद मिलेगी। तीसरा कदम— एक साझेदारी बनाना है। एक उद्यमी के रूप में सफल होने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी आपको आवश्यकता होगी और आपको उन चीजों को प्रदान करने के लिए किसी की आवश्यकता भी संभवतः हो सकती है। उन लोगों के साथ सही साझेदारी बनाएं, जो आपके सपने और सफलता की महत्वाकांक्षा को साझा करते हैं। चौथा कदम— कृषि के क्षेत्र में 'धमाकेदार' के साथ अपना नया 'स्टार्ट-अप' व्यवसाय शुरू करना है। आपको एक बहुत मजबूत और ठोस व्यवसाय योजना की आवश्यकता है। आपको कुछ जोखिम भी उठाने पड़ सकते हैं। यह जानना कि आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, सही व्यवसाय योजना बनाना बहुत कठिन काम नहीं है। आपके लिए यह याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि साझेदारी आपके कृषि व्यवसाय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि आप वास्तव में सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जो भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उसका ठीक से उपयोग करेंगे।



कैसे बनाएं अभिलेखीय विज्ञान में करियर

प्रत्येक स्थान का इतिहास हजारों पांडुलिपियों, अभिलेखों, शिलालेखों, दस्तावेजों आदि में अंतर्निहित है, इन अद्वितीय अभिलेखों को वैज्ञानिक रूप से संरक्षित और अभिलेखीय अभिलेख या आर्काइवल रिकॉर्ड्स कहा जाता है, जो किसी विशेष क्षेत्र और समाज के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। आमतौर पर लोग म्यूजियम, आर्काइव्स और लाइब्रेरी को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जो सांस्कृतिक विरासत के संग्रह और संरक्षण से संबंधित हैं। यह तीनों ही इतिहास को संरक्षित रखने में मदद करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। जहां, संग्रहालय ऐतिहासिक कलाकृतियों और वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं पुस्तकालय में प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि को रखा जाता है, जबकि आर्काइव्स अभिलेखों पर ध्यान केंद्रित करने में माहिर हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बताते हैं कि अभिलेखीय विज्ञान में करियर कैसे बनाएं—

क्या होता है काम

करियर एक्सपर्ट कहते हैं कि एक व्यक्ति जो अभिलेखागार में काम करता है, उसे पेशेवर रूप से एक अभिलेखागार या आर्काइवल के रूप में जाना जाता है। अभिलेखागार ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स संग्रह का प्रबंधन करने के लिए मानकों का पालन करते हैं। वे उन अभिलेखों का मूल्यांकन, संग्रह, आयोजन, संरक्षण और रखरखाव करते हैं, जिनके पास अतीत की विश्वसनीय यादों के रूप में स्थायी मूल्य होते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय और स्थानीय अभिलेखागार, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, व्यवसायों, आदि में दस्तावेजीकरण के लिए जिम्मेदार हैं, वे कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड्स को संरक्षित और सुलभ बनाते हैं।

शैक्षणिक योग्यता

करियर एक्सपर्ट के अनुसार, अधिकांश कॉलेज और विश्वविद्यालय सूचना विज्ञान के साथ एक सहायक विषय के रूप में अभिलेखीय विज्ञान पढ़ाते हैं। वहीं, भारत में कुछ संस्थान ऐसे भी हैं, जो अभिलेखीय विज्ञान में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जैसे कि अभिलेखागार में पीजी प्रमाणपत्र, अभिलेखागार अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अभिलेखागार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अभिलेखागार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और अभिलेखागार और प्रबंधन और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि।

व्यक्तिगत गुण

करियर एक्सपर्ट कहते हैं कि एक आर्काइविस्ट में बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के अलावा एनालिटिकल एंड रिसर्च स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और आर्गनाइजेशनल एबिलिटी होना बेहद जरूरी है। उन्हें धैर्य रखने के अलावा

करियर एक्सपर्ट कहते हैं कि एक व्यक्ति जो अभिलेखागार में काम करता है, उसे पेशेवर रूप से एक अभिलेखागार या आर्काइवल के रूप में जाना जाता है। अभिलेखागार ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स संग्रह का प्रबंधन करने के लिए मानकों का पालन करते हैं। वे उन अभिलेखों का मूल्यांकन, संग्रह, आयोजन, संरक्षण और रखरखाव करते हैं, जिनके पास अतीत की विश्वसनीय यादों के रूप में स्थायी मूल्य होते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय और स्थानीय अभिलेखागार, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, व्यवसायों, आदि में दस्तावेजीकरण के लिए जिम्मेदार हैं, वे कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड्स को संरक्षित और सुलभ बनाते हैं।

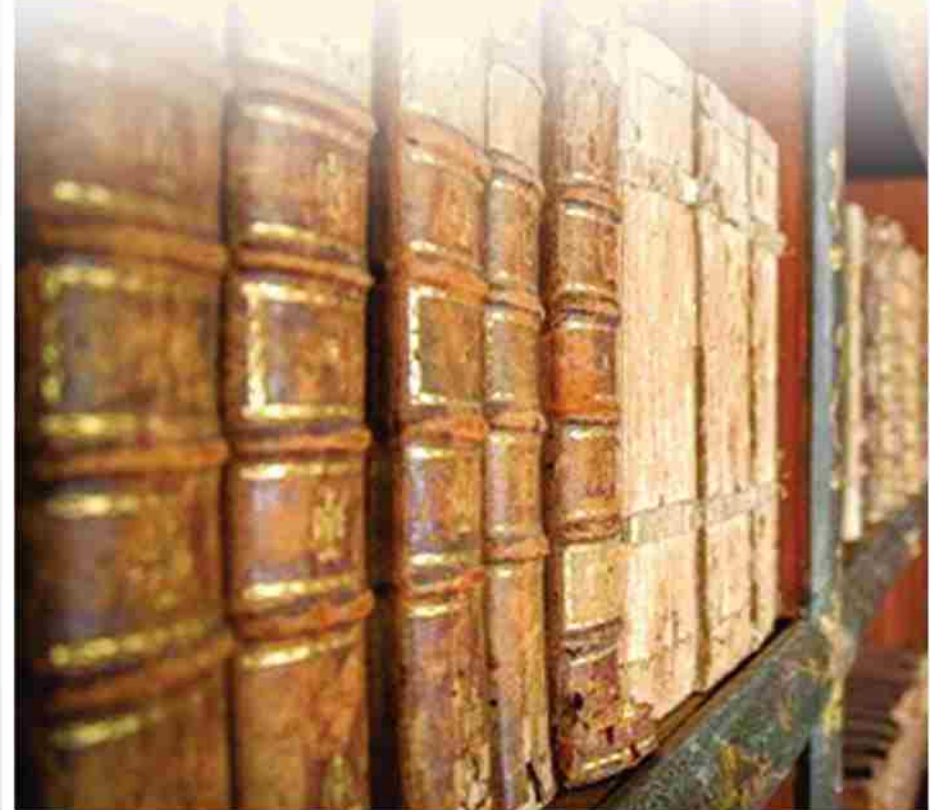
स्टीक, पूरी तरह से समझने और क्या जानकारी रखने के बारे में अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होने की आवश्यकता है। उन्हें एक सुव्यवस्थित और व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए, जानकारी को निजी रखने और दबाव में अच्छी तरह से काम करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा, एक आर्काइविस्ट को कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी सही तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए।

संभावनाएं

आर्काइविस्ट विभिन्न संगठनों जैसे संग्रहालयों, सरकारी एजेंसियों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, औद्योगिक और वाणिज्यिक फर्मों, ऐतिहासिक सोसाइटी, निगमों और अन्य कई संस्था में काम कर सकते हैं। वहीं, सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश करने वालों को संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को पास करना होगा। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, जो राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और अभिलेखागार का प्रबंधन करता है, अपनी विभिन्न इकाइयों में योग्य उम्मीदवारों को नौकरी के विभिन्न अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र में एक फ्रेशर शुरुआती वेतन 10000 रुपये से लेकर 15000 रुपये प्रति माह तक कमा सकता है। अनुभव और योग्य पेशेवर प्रति माह लगभग 20,000 रुपये का वेतन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अनुभव बढ़ने के साथ-साथ आपकी आमदनी भी बढ़ती है।

प्रमुख संस्थान

- नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
- पटना यूनिवर्सिटी, पटना
- महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर
- द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु



कनाडा में चाकू घोंपने की घटना के संदिग्ध की पुलिस कर रही है तलाश

रेंजिना (कनाडा)। कनाडा के सस्कचेवान प्रांत में एक स्थानीय जातीय समुदाय और पास के एक अन्य शहर में चाकूबाजी कर 10 लोगों की हत्या को अजाम देने वाले संदिग्धों की पुलिस समूह प्रांत में तलाश कर रही है। संदिग्धों की चाकूबाजी में 15 लोगों के घायल होने की भी खबर है। जिसके चलते 'जेम्स स्मिथ क्री नेशन' को राज्य में आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी है। इस घटना ने निकटवर्ती वल्टन गांव के लोग दहशत में है। वल्टन की निवासी रुबी वरर्स ने कहा, 'शहर में अब कोई वैन से नहीं सो पाएगा। अब लोग अपने-अपने घरों के दरवाजे खोलने से डरेंगे।' पुलिस ने हालांकि कहा कि जिस वाहन में दोनों संदिग्धों के होने की संभावना है उसे रेंजिना में देखा गया है। जिस जगह यह घटना हुई है और जहां समुदाय के लोग निवास करते हैं वह रेंजिना से करीब 33.5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। रेंजिना पुलिस प्रमुख इवान ब्रे ने कहा कि उनका अब भी मानना है कि संदिग्ध रेंजिना में ही है। आरसीएमपी ने ट्विटर पर एक संदेश में कहा, 'अगर आप रेंजिना क्षेत्र में हैं तो सावधानी बरतें और किसी जगह आश्रय लेने पर विचार करें। सुरक्षा स्थान नहीं छोड़ें, संदिग्ध व्यक्तियों के पास नहीं जाएं, किसी अनजान को अपने पास नहीं बुलाएं तथा संदिग्ध व्यक्तियों, आपात स्थितियों की सूचना पुलिस को दें।' संदिग्धों की पहचान 31 वर्षीय डेविडन सैंडरसन और 30 वर्षीय माइल्स सैंडरसन के रूप में की गई है। आरसीएमपी सस्कचेवान की सहायक आर्क्टिक रोज ब्लैकमोर ने कहा कि कुछ लोगों को संदिग्धों ने निशाना बनाया था, लेकिन अन्य लोगों पर अनायास हमला किया गया था। अधिकारी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि हमले क्यों किए गए। हालांकि, 'फेडरेशन ऑफ सॉवरेन इंडीजिनस नेशंस' के प्रमुख ने बयान जारी कर आशंका जताई कि चाकूबाजी की इन घटनाओं का संबंध मादक पदार्थ से हो सकता है। तीन समुदायों 'जेम्स स्मिथ क्री नेशन', 'चाकस्तायपासिन बैंड' और 'पीटर वेपमैन बैंड' के निर्वाचित नेताओं ने स्थानीय आपातकाल की घोषणा की और दो आपातकालीन संचालन केंद्र खोले। चाकस्तायपासिन के प्रमुख कैल्विन सैंडरसन - जो संदिग्धों से संबंधित नहीं है - ने कहा कि हर कोई दुखद घटनाओं से प्रभावित हुआ है। सैंडरसन ने कहा, 'वे हमारे रिश्तेदार, दोस्त थे। यह बहुत भयानक है।' 'फेडरेशन ऑफ सॉवरेन इंडीजिनस नेशंस' के प्रमुख बॉबी कैमरन ने कहा, 'यह विनाश है जिसका हम सामना कर रहे हैं। हानिकारक अवैध मादक पदार्थ हमारे समुदायों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सभी अधिकारियों को सलाह है कि वे अपने प्रमुखों और परिषदों एवं उनके सदस्यों से निर्देश लें ताकि हमारे लोगों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ समुदायों का निर्माण किया जा सके।

जिम्बाब्वे में खसरे के प्रकोप से अब तक 700 बच्चों की हुई मौत

हरारे (जिम्बाब्वे)। जिम्बाब्वे में खसरे के प्रकोप से जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ कर लगभग 700 हो गई है। यह जानकारी देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। कुछ लोग ऐसे देश में टीकाकरण को अनिवादी बनाने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं जहां 1.5 करोड़ की आबादी पर आधुनिक चिकित्सा विरोधी धार्मिक संप्रदायों का प्रभाव है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सप्ताहांत में घोषणा की थी कि अप्रैल में खसरे का प्रकोप शुरू होने के बाद से रोग से 698 बच्चों की मौत हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि इनमें से 37 मौतें एक सितंबर को एक ही दिन में हुईं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसने चार सितंबर तक 6,291 मामले दर्ज किए हैं। नवीनतम आंकड़े लगभग दो सप्ताह पहले घोषित मृतक संख्या से चार गुना से अधिक हैं, जब मंत्रालय ने कहा था कि '157 बच्चों ने बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। मंत्रालय ने कहा कि इनमें से अधिकांश बच्चों की उनके परिवार की धार्मिक मान्यताओं के कारण टीके नहीं लगाये गये थे। मेडिकल एंड डेंटल प्राइवेट प्रैक्टिसनर्स आफ जिम्बाब्वे एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. जोहान्स मारिसा ने सोमवार को बताया कि सरकार को बड़े पैमाने पर चल रहे टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए और विशेष रूप से टीकाकरण विरोधी धार्मिक समूहों को लक्षित करते हुए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। मारिसा ने कहा, 'सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़तापूर्वक उपायों पर भी विचार करना चाहिए कि किसी को भी अपने बच्चों का टीकाकरण कराने से इनकार करने की अनुमति नहीं हो।' उन्होंने सरकार से 'खसरा जैसी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण को अनिवादी बनाने वाले कानून बनाने पर विचार करने' का आग्रह भी किया। यूनिसेफ ने सोमवार को कहा कि वह खसरे के कारण बच्चों की मौतों की संख्या से 'बहुत चिंतित' है। एजेंसी ने कहा कि वह टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से इस रोग के प्रकोप से निपटने में सरकार की सहायता कर रही है। खसरे का प्रकोप पहली बार अप्रैल की शुरुआत में पूर्वी मानिकलैंड प्रांत में सामने आया था और तब से यह देश के सभी हिस्सों में फैल गया है। सूचना मंत्री मॉनिका मुत्सवांगवा ने अग्रसर के साथ था कि ऐसे कई बच्चों की मौत हुई है जिन्हें टीका नहीं लगाया गया था। जिम्बाब्वे के मंत्रिमंडल ने रोग के प्रकोप से निपटने के लिए आपदाओं से निपटने में इस्तेमाल किया जाने वाला कानून लागू किया है। सरकार ने 6 महीने से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया है।

चीन के सिचुआन प्रांत में 6.8 तीव्रता का भूकंप जिसमें हुई 21 लोगों की मौत

बीजिंग। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत की लुडिंग काउंटी में सोमवार को 6.8 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गयी। यह प्रांत पहले ही कोविड-19 के बढ़ते मामलों और अभूतपूर्व सूखे की समस्या से जूझ रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी 'शिनहुआ' ने चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के हवाले से बताया कि भूकंप स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर आया और भूकंप का केंद्र 29.59 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 102.08 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जमीन से 16 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। भूकंप का केंद्र लुडिंग काउंटी से 39 किलोमीटर दूर स्थित था और भूकंप के केंद्र के पांच किलोमीटर के दायरे में कई गांव अति हैं। भूकंप के झटके सिचुआन प्रांत की राजधानी वेंगदु में भी महसूस किए गए, जो भूकंप के केंद्र से 226 किलोमीटर दूर स्थित है। चीन के सांख्यिक मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो में चेगु में इमारतों को हिलते हुए देखा जा सकता है। अभी किसी इमारत को नुकसान पहुंचने की जानकारी नहीं है। सिचुआन प्रांत तिब्बत के पड़ोस में स्थित है और भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। इस प्रांत में 2008 में 8.2 की तीव्रता वाला विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें करीब 69,000 लोगों की मौत हो गयी थी। प्रांत में 2013 में सात की तीव्रता के भूकंप में 200 लोगों की जान वली गयी थी। चेगदु में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है। निवासियों को घरों में रहने के लिए कहा गया है और हर घर से केवल एक व्यक्ति को प्रतिदिन आवश्यक सामान खरीदने के लिए बाहर निकलने की अनुमति है।

सेना के खिलाफ बयानबाजी को लेकर अदालत ने इमरान खान को लगाई फटकार

इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सेना के खिलाफ बयानबाजी को लेकर सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फटकार लगाई और कहा कि देश में जारी 'सत्ता की होड़' के लिए सब कुछ दाय पर नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने आग्रह किया कि खान की बयानबाजी के कारण उनके अभिव्यक्ति के अधिकार को संविधान के तहत बरकरा रखना संभव नहीं हो पाएगा। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनवरुल मीनहान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इसाफ (पीटीआई) पार्टी के भाषणों के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति मिनहान रविवार को एक सार्वजनिक रेली में खान की टिप्पणी से नाराज थे, जिसके लिए सरकार पहले ही उनकी आलोचना कर चुकी है। सेना ने भी टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे सत्यकारी करार दिया था। खान ने रविवार को फैसलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार अपनी पसंद का सेना प्रमुख नियुक्त करने के लिए चुनाव में देरी कर रही है। उन्होंने कहा था, '(आसिफ अली) जरदारी और नवाज (शरीफ) अपनी पसंद का अगला सेना प्रमुख नियुक्त करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जनता को पैसा चोरी किया है।' खान ने कहा था, 'उन्हें डर है कि जब देशभक्त सेना प्रमुख आएगा, तो वह उनसे उनके द्वारा की गई लूट के बारे में पूछेगा।' 'डॉन' समाचार पत्र की खबर के अनुसार सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने फैसलाबाद की रेली में की गई खान की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए पूछा, 'आ सार्वजनिक रूप से कैसे कह सकते हैं कि कोई सेना प्रमुख देशभक्त है या नहीं?' न्यायमूर्ति मिनहान ने कहा कि सशस्त्र बल के जवान शहीद हो रहे हैं और आप (इमरान खान) उनका मनोबल गिरा रहे हैं।' उन्होंने 'पीटीआई' के वकील से यह भी पूछा कि (उनकी पीटी) संवैधानिक संरचना को नुकसान क्यों पहुंचा रही है। उन्होंने कहा, 'आप अपने बयानों से केवल परेशानियों को बढ़ा रहे हैं।' न्यायाधीश ने कहा कि हालिया बयान संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के अंतर्गत ही नहीं आता। उन्होंने कहा, 'इस तरह के बयान देकर आप प्रतिबंध से कैसे बच सकते हैं।' न्यायाधीश ने कहा, 'बया हम सत्ता की होड़ के लिए सब कुछ दाय पर लगा सकते हैं?' उन्होंने कहा कि जो चीजें चल रही हैं, उनके कारण अदालत संरक्षित देने की कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कम्मर जावेद बाजवा नवंबर के अंतिम सप्ताह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वह छह साल से इस पद पर हैं।



दोहा में कटारा हॉटिंग व फालकल प्रदर्शनी में भाग लेती हुई कंपनियां।

बकिंघम पैलेस की बजाय स्काटलैंड से क्यों हुआ नए पीएम का ऐलान, -लिज ट्रस ने क्वीन एलिजाबेथ की मौजूदगी में ली शपथ

लंदन (एजेंसी)।

कंजर्वेंटव पार्टी की नेता लिज ट्रस ने क्वीन एलिजाबेथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने औपचारिक रूप से उन्हें एक नई सरकार बनाने के लिए कहा गया। जिसके बाद लिज ट्रस ने आज दोपहर स्काटलैंड के बाल्मोरल कैसल में पदभार ग्रहण किया। महारानी के 70 साल के शासनकाल में यह पहली बार था कि सत्ता का हस्तांतरण लंदन के बकिंघम पैलेस के बजाय बाल्मोरल में हुआ। गर्मियों के इस मौसम में 96 वर्षीय क्वीन एलिजाबेथ स्काटलैंड के वलमोरल कासल में हैं। इसलिए परंपरा से अलग इस बार स्काटलैंड से नए पीएम का ऐलान हुआ।

नई सरकार कब से?

शाही कार्यक्रमों का आधिकारिक रिकॉर्ड रखने वाला कोर्ट सर्कुलर ने नए पीएम की नियुक्ति की जानकारी दी। अब नई पीएम लंदन लौटेंगी। इसके बाद 47 वर्षीय ट्रस लंदन स्थित 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचकर प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला भाषण देंगी और इसके बाद कुछ प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों के नाम की घोषणा करेगी।



7 सितंबर को नए कैबिनेट की ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के चैंबर में बैठक होगी। उसी दिन शाम के 4:30 बजे नए पीएम का विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर से आमना सामना होगा।

कैसा होगा नया कैबिनेट

ब्रिटेन के मीडिया की कुछ खबरों के मुताबिक मंत्रिमंडल में बदलाव के साथ ही डाउनिंग स्ट्रीट में भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है तथा जॉनसन के कार्यकाल में रहे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।

नये मंत्रिमंडल में कारोबार मामलों के मंत्री द्वासी क्लारिंग का नाम वित्त मंत्री के लिए चुन रहा है, वहीं शिक्षा मंत्री जेम्स क्लोवेलरी को विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसे अब तक ट्रस खुद संभाल रही थीं। इनके अलावा ब्रिटिश पाकिस्तानी साजिद जाविद के साथ ही नदीम जहावी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री बेन वालेस, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री एनी-मैरी ट्रेवेल्यान और संस्कृति मंत्री एन डोरजी अपने पदों पर बने रह सकते हैं।

चीन ने 6.5 करोड़ लोगों पर लगाई लॉकडाउन की पाबंदी

बीजिंग, 1 चीन ने अपने साढ़े छह करोड़ नागरिकों को सख्त कोविड-19 प्रतिबंधों के तहत लॉकडाउन में रखा है और देश में आगामी राष्ट्रीय अवकाशों के दौरान घरेलू यात्रा को हतोत्साहित किया जा रहा है। चीनी कारोबारी पत्रिका 'काइशिंग' द्वारा रविवार देर रात प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक देश की सात प्रांतीय राजधानियों समेत 33 शहर पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन के दायरे में हैं जिससे यहां रहने वाले साढ़े छह करोड़ लोग प्रभावित हैं। पत्रिका ने कहा कि 103 शहरों में संक्रमण देखा गया है और यह 2020 में महामारी के शुरुआती दिनों के बाद से सर्वाधिक संख्या है। संक्रमण के अपेक्षाकृत कम मामलों के बावजूद अधिकारी 'शून्य कोविड' की नीति का पालन कर रहे हैं जिसमें लॉकडाउन, पृथक्वास और किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने पर संदिग्धों को घरों में रखने की बात कही गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 1.4 अरब की आबादी वाले चीन में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,552 नए मरीज सामने आए। दक्षिणपश्चिमी चेगदू शहर की लगभग 2.1 करोड़ आबादी में अधिकतर लोग अपने फ्लैट या रिहाइशी परिसरों में सिमटे हैं, जबकि पूर्वी बंदरगाह शहर तियानजिन में कोविड-19 के 14 मामले सामने आने के बाद अब ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। चेगदू के डिग्लोई और शिनजिन जिलों में करीब 10 लाख लोगों को लॉकडाउन के दायरे से बाहर किया गया है। बुधवार को तीन और दौर का व्यापक परीक्षण किया जाएगा। सभी स्कूल बंद हैं और कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन हो रहा है।

भारतीय मूल की हैं सुएला ब्रेवरमैन, बन सकती हैं ब्रिटेन की अगली गृह मंत्री

काठमांडू (एजेंसी)।



ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चुनाव के नतीजे आ गए हैं। पूर्व विदेश मंत्री लिज ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हरा दिया। जानकारी के मुताबिक लिज ट्रस आज ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगी। इन सब के बीच खबर यह भी है कि बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही बोरिस जॉनसन की सरकार में गृह मंत्री पद संभाल रही भारतीय मूल की प्रीति पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में लिज ट्रस अपने कैबिनेट में नए नामों को शामिल कर सकती हैं। इसी कड़ी में एक नाम खूब सुर्खियों में है। वह नाम है सुएला फर्नांडीस ब्रेवरमैन का। माना जा रहा है कि सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन कैबिनेट में प्रीति पटेल का स्थान ले सकती हैं। उन्हें लिज ट्रस अपने कैबिनेट में यूके की गृह मंत्री बना सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो प्रीति पटेल और साजिद जाविद के बाद ब्रेवरमैन यूके की गृह मंत्री बनने वाली तीसरी अल्पसंख्यक होंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि सुएला फर्नांडीस ब्रेवरमैन का नाता भारत से है। जी हां, सुएला ब्रेवरमैन भी भारतीय मूल की हैं। उनका नाता भारत के गोवा से है। वह भारत के गोवा की रहने वाली हैं। इस समय एटर्नी जनरल के पद पर काबीज हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1980 को हुआ था। उनके पिता का नाम क्रिस्टी और माता का नाम उमा फर्नांडीस था। यह दोनों की भारतीय मूल के ही थे। इस चुनाव में सुएला ब्रेवरमैन ने लिज ट्रस का समर्थन किया था। यही कारण है कि वह गृह मंत्री के पद के लिए सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं। ब्रेवरमैन के पिता एक हाउसिंग एसोसिएशन के लिए काम करते थे, वहीं, उनकी माता नर्स और काउंसिलर के तौर पर काम करती थीं। ब्रिटेन प्रधानमंत्री पद के चुनाव में जब लिज ट्रस पीछे हो रही थीं, उस वक सुएला ब्रेवरमैन ने उनका भरपूर समर्थन किया था।

युद्धग्रस्त यूक्रेन के परमाणु संयंत्र में तनावपूर्ण स्थिति अभी तक बरकरार

कीव (एजेंसी)।

यूक्रेन में स्थित यूरोप के सबसे बड़े जर्पोरिजिया परमाणु संयंत्र में सोमवार को भी स्थिति तनावपूर्ण रही। संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षक रूसी हमले के कारण संकट में आए इस यूक्रेनी स्थल पर संचालित आपदा को टालने के अपने प्रयासों पर मंगलवार को रिपोर्ट देंगे। रूसी सेना ने यूक्रेनी बलों पर संयंत्र में उकसाने वाली कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि कीव के बलों ने ड्रोन से संयंत्र के क्षेत्र को रिववार को निशाना बनाया, लेकिन रूसी बल इस ड्रोन को गिराने में कामयाब रहे। मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी बलों ने रात में दो भारी मीटलवर्टी शहर एनेरहोदार पर भी गोलाबारी की। क्रेमलिन के बलों ने मार्च की शुरुआत में इस संयंत्र पर कब्जा कर लिया था। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर संयंत्र को खतरों में डालने का आरोप लगाया है। संयंत्र में यूक्रेनी कर्मियों ने काम जारी रखा है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों ने एक हफ्ते के अभियान के तहत पिछले सप्ताह संयंत्र तक पहुंचने के लिए युद्ध क्षेत्र से यात्रा की। यूक्रेन के सरकारी परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालक एनेरहोएटम ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के छह में से चार निरीक्षकों ने अपना काम पूरा कर लिया है और वे स्थल से चले गए हैं। एनेरहोएटम ने बताया कि दो विशेषज्ञ संभवतः स्थायी रूप से संयंत्र में रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षक मंगलवार को सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट देंगे। ऊर्जा बजारों में खलबली मचाने वाले युद्ध के कारण संयंत्र काफी हद तक पंगु हो गया है।

नेपाली राष्ट्रपति भंडारी ने थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया

काठमांडू (एजेंसी)।



नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सोमवार को भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक निवास 'शीतल निवास' में एक विशेष समारोह में जनरल पांडे को मानद उपाधि से सम्मानित किया। नेपाल और भारत के थल सेना प्रमुखों द्वारा एक-दूसरे के देश की यात्राएं करने और एक-दूसरे देश के थल सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की लंबी परंपरा रही है। यह परंपरा 1950 में शुरू हुई थी।

जनरल पांडे रविवार को पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर यहां पहुंचे। अपनी इस यात्रा के दौरान वह देश के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे और दोनों पड़ोसी देशों के बीच के रक्षा संबंधों को

मजबूत बनाने पर जोर देंगे। जनरल मनोज पांडे को सोमवार को सेना मुख्यालय में गाई ऑफ ऑनर दिया गया। नेपाली सेना ने एक टवीट में कहा, भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने नेपाली थल सेनाध्यक्ष जनरल प्रभु राम शर्मा को विभिन्न गैर-घातक सैन्य साजोसामान सौंपे। नेपाली सेना मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार भारत ने चार घोड़े, 10 एमपीवी (बारूदी सुरंगों से सुरक्षित वाहन) और कुछ चिकित्सा उपकरण सहित गैर-घातक साजोसामान सौंपे। यह सहायता 22.38 करोड़ नेपाली रुपये (17,51,821

अमेरिकी डॉलर) के बराबर है। सूत्रों ने बताया कि यह भारतीय सेना द्वारा दी गई विशेष सन्धि है, जिसमें 60 प्रतिशत अनुदान सहायता शामिल है। नेपाली सेना ने एक अन्य टवीट में कहा, भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने सेना पैवेलियन में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जनरल पांडे मंगलवार को नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और अन्य वरिष्ठ सैन्य और नागरिक अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। उनकी इस यात्रा के दौरान अनिपण योजना के तहत नेपाल से गोरखाओं को भारतीय सेना में शामिल करना मुंबई पर भी चर्चा होने की संभावना है। वह आठ सितंबर को काठमांडू से नयी दिल्ली रवाना होंगे। जनरल पांडे के साथ भारतीय थल सेना के आर्मी वाइस् वेल्फेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष अर्चना पांडे भी आई हैं।

शी चिनफिंग जल्द ही कजाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे

बीजिंग (एजेंसी)।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 14 सितंबर को कजाकिस्तान की यात्रा करेंगे और पड़ोसी देश उज्बेकिस्तान में आगे लिये आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। यह चिनफिंग की कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद करीब छह साल में पहली विदेश यात्रा होगी। कजाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ऐबक स्मिदियाव ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी की कजाकिस्तान राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकतयेव के निमंत्रण पर कजाकिस्तान गणराज्य की राजकीय यात्रा इस साल 14 सितंबर को करने की योजना है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने उनके हवाले से कहा कि यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने कई सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है। शी के जनवरी 2020 के बाद पहली बार चीन से बाहर जाने की योजना के बारे में बीजिंग में कोई पुष्टि नहीं हुई है। म्यांमार आखिरी देश था जहां की यात्रा शी ने 17-18 जनवरी, 2020 को की थी। उनकी वापसी के कुछ ही दिनों बाद, चीन ने वुहान में कोरोना वायरस के बड़े

पैमाने पर प्रकोप की घोषणा की थी, जो बाद में एक बड़े पैमाने पर वैश्विक महामारी में बदल गया था। इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में लाखों मौतें हुईं। तब से 69 वर्षीय शी चीन से बाहर नहीं निकले हैं और वैश्विक कार्यक्रमों में डिजिटल माध्यम से शामिल हुए हैं। शी की विदेश यात्रा का पहला संकेत हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से आया, जिन्होंने अपनी 25 जुलाई की यात्रा के दौरान शी से मुलाकात की थी और उन्हें नवंबर में बाली में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया था।

विडोडो ने बाद में कहा कि शी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर लगातार चुप्पी साधे रखी है। इसके लेकर संदेह है कि क्या शी 15-16 सितंबर को होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे क्योंकि यह कम्युनिस्ट पार्टी आफ चाइना (सीपीसी) कांग्रेस से पहले होगा। राजनियंत्रण सूत्रों का कहना है कि शी की कजाकिस्तान यात्रा से उनके उज्बेकिस्तान के समरकंद में आठ देशों के एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी

शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। दोनों नेताओं ने अपनी भौतिक भागीदारी की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। बीजिंग मुख्यालय वाला एससीओ आठ सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा समूह है जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद, भारत मध्य एशियाई गणराज्यों के प्रभावशाली समूह की अध्यक्षता संभालेगा। यदि मोदी और शी शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं, तो दोनों नेता 2019 में ब्रिक्स

(ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) से इतर ब्रासीलिया में अपनी बैठक के बाद पहली बार आमने-सामने हो सकते हैं। तब से दोनों पक्षों के बीच संबंधों में मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर खिंटना आ गई है। सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के परिणामस्वरूप, दोनों पक्षों ने पिछले साल पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट से और गोगरा क्षेत्र से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की थी। गतिरोध हल करने के लिए दोनों पक्षों ने अब तक कमांडर स्तर की 16 दौर की बातचीत की है।



अमेरिकी ओपन में किर्गियोस ने मेदवेदेव को हराया

न्यूयॉर्क। अमेरिकी ओपन टेनिस में रुस के डेनिल मेदवेदेव हार के साथ ही बाजार हो गये हैं। विश्व के नंबर एक वरियता प्राप्त खिलाड़ी मेदवेदेव को ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस ने चौथे दौर में 7-6 (11), 3-6, 6-3, 6-2 से हराकर सनसनी फैला दी। किर्गियोस का मुकाबला अब सेमीफाइनल में केरन खचानोव से होगा। किर्गियोस ने मेदवेदेव के खिलाफ 3-1 की बढ़त के साथ अच्छे शुरुआत की। इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने करीब तीन घंटे तक चले मुकाबले में मेदवेदेव पर चौथी जीत हासिल की। अब इस हार से मेदवेदेव की नंबर एक एटीपी रैंकिंग भी खिसक जाएगी। अब स्पेन के रफल नडाल, कार्लोस अल्कराज या नार्वे के केस्पर रूड में से कोई एक नंबर-एक बन सकता है।

पायस-यशस्विनी की जोड़ी ने एशियाई जूनियर टेबल टेनिस में स्वर्ण जीता

नयी दिल्ली,

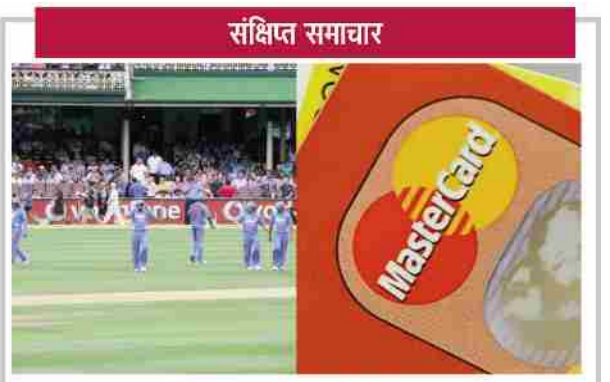
पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े ने चीन की हान शिनयुआन और किन युसुआन की चीनी जोड़ी को 3-2 से हराकर लाओस में एशियाई जूनियर और डेट चैंपियनशिप के मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीत कर अपने अभियान का अंत किया। भारतीय जोड़ी ने 11-9, 11-1, 10-12, 7-11, 11-8 से जीत दर्ज की। यह एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर खिलाड़ियों का पहला स्वर्ण पदक है। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों ने तीन कांस्य पदक भी जीते। यह पदक उमने लड़कों के अंडर-19 युगल, लड़कियों के अंडर-19 एकल और लड़कों की अंडर-19 टीम स्पर्धा

में जीते। इस तरह से भारतीय जूनियर खिलाड़ियों ने चार पदक हासिल किए। पायस और यशस्विनी की शीर्ष वरियता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करके पहले दोनों गेम जीते लेकिन चीनी जोड़ी ने भी इसके बाद अच्छी वापसी की और अगले दोनों गेम जीतकर मुकाबले को निर्णायक गेम तक खींच दिया जिसमें भारतीयों ने दमदार प्रदर्शन किया। कर्नाटक की शीर्ष वरियता प्राप्त यशस्विनी ने लड़कियों के अंडर-19 एकल में क्वार्टर फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन सेमीफाइनल में वह चीन की चेंग यी से सीधे गेम में 13-11, 11-9, 11-4, 11-3 से हार गई। पायस ने भी दिल्ली के अपने साथी



यशारा मलिक के साथ मिलकर क्वार्टर फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन अपनी इस लय को वे सेमीफाइनल में बरकरार नहीं रख पाए और लड़कों के अंडर-19

युगल में जापान के युता लिमुरा और यूही सकाई से 11-8, 11-7, 12-14, 11-6 से हार गए। इस तरह से उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा।



मास्टरकार्ड अब भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक होगा

मुम्बई। मास्टरकार्ड अब भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने देश में होने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू टूर्नामेंट के लिए मास्टरकार्ड को पीटीएम की जगह नया खिताबी प्रायोजक बनाया है। इससे पहले पीटीएम ने प्रायोजन अधिकारों के हस्तांतरण को लेकर बीसीसीआई पदाधिकारियों के साथ बात की थी, जिसके बाद से ही प्रायोजक में बदलाव होना तय नजर आ रहा था। बीसीसीआई के अनुसार, अब मास्टरकार्ड पुरुषों के अलावा महिला क्रिकेट मुकाबले के लिए स्वदेश में होने वाले सभी मैचों का प्रायोजक होगा। बीसीसीआई द्वारा आयोजित ईरानी टूर्नामेंट, दलीप टूर्नामेंट और रणजी टूर्नामेंट जैसे घरेलू क्रिकेट मैचों के साथ-साथ देश में होने वाले सभी जूनियर क्रिकेट (अंडर-19 और अंडर-23) मुकाबलों के लिए भी मास्टरकार्ड ही खिताबी प्रायोजक होगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय स्रीज के अलावा बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे भारत को एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय टीम बनाने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए घरेलू मुकाबलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

तेजी से बदल रहा है क्रिकेट परिदृश्य, संतुलन बनाने की जरूरत: विलियमसन

केयर्स। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का मानना है कि कई टी20 आने से विश्व भर में क्रिकेट का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है तथा फेंचइजी क्रिकेट और राष्ट्रीय टीम की तरफ से खेलने के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। विलियमसन का यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि दुनियाभर के क्रिकेटर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वजह टी20 लीग में खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'यह मुश्किल स्थिति है क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है।' विलियमसन ने कहा, 'ऐसा लगता है कि यह खेल के परिदृश्य को लेकर एक आंदोलन है। हर मामला पूरी तरह से भिन्न है और प्रत्येक मामले की अपनी व्यापकता आवश्यकताएं हैं।' उन्होंने कहा, 'फेंचइजी क्रिकेट में कई अलग तरह के आयोजन हो रहे हैं और खिलाड़ी अपने करियर को लेकर फैसला कर रहे हैं। इसे देखकर लगता है संतुलन बनाना जरूरी है।' हाल में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेट बोल्ट अपने केंद्रीय अनुबंध से हट गए थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने और विश्व भर में टी20 क्रिकेट खेलने को लेकर ऐसा फैसला किया। इसके तुरंत बाद बोल्ट को विंग बैश लीग (बीबीएल) की फेंचइजी मेलबर्न स्टार्स ने अपनी टीम से जोड़ दिया था। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया और उन्हें भी बीबीएल फेंचइजी एडिलेड स्टार्कर्स ने अपनी टीम में ले लिया।



SURESH RAINA

205 MAT	5528 RUNS	32.51 AVE	136.73 SR
25 WKTS	44.72 AVE	7.38 ER	109 CT

सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास

नई दिल्ली।

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की जिससे वह विदेशों में होने वाली टी20 लीग में खेलने के लिए योग्य हो गए हैं। इस 35 वर्षीय खिलाड़ी ने 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की घोषणा करने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। रैना ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 2021 में खेलना जारी रखा था लेकिन 2022 के सत्र से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें अपनी टीम में नहीं रखा था। रैना ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड, उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ और चेन्नई सुपर किंग्स का आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, 'अपने देश और राज्य उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना मेरे



लिए सम्मान की बात है। मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करता हूँ। भारत या घरेलू स्तर पर सक्रिय खिलाड़ी विदेशी लीग में भाग नहीं ले सकते हैं और ऐसे में रैना के लिए विश्वभर की टी20 लीग में खेलने के लिए संन्यास लेना जरूरी था। रैना ने अपना आखिरी अफ्रीका की नई टी20 लीग में खेलते हुए देखा जा सकता है। इस लीग की सभी छह टीमों का स्वागत आईपीएल के मालिकों के पास है। रैना ने अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच अक्टूबर 2021 में चेन्नई की तरफ से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अबू धाबी में खेला था। भारत की तरफ से रैना ने 18 टेस्ट, 226 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और 78 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे। वह 2011 में विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य

भारतीय बैडमिंटन संघ पदक ने पदक विजेताओं के लिए घोषित किये पुरस्कार

लक्ष्य और सिंधु को 20-20 लाख रुपये मिलेंगे

नई दिल्ली।

भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) ने राष्ट्रमण्डल खेलों के साथ ही विश्व चैंपियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बीएआई ने विजेता खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए 1.5 करोड़ रुपये के पुरस्कारों की घोषणा की है। महासंघ के अध्यक्ष हिमंता विश्व सरमा ने पुरस्कार राशि की घोषणा करते हुए कहा, 'हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों ने लगातार देश का गौरव बढ़ाया है और यह नकद पुरस्कार पिछले दो वर्षों में उनकी शानदार उपलब्धियों को सम्मान देने का छोटा सा प्रयास भर है।' राष्ट्रमण्डल खेलों के पुरुष और महिला एकल में स्वर्ण विजेता लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु को 20-20 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी की पुरुष युगल जोड़ी को

स्वर्ण जीतने के लिए 25 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। लक्ष्य को विश्व चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीतने के लिए भी पांच लाख रुपये दिये जाएंगे। वहीं गायत्री गोपीचंद और त्रीसा जॉली की युवा महिला युगल जोड़ी को कांस्य पदक जीतने पर 7.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत को भी बर्मिंघम में अपने पुरुष एकल कांस्य पदक के लिए पांच लाख रुपये जबकि स्पेन के ह्युएलवा में 2021 बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक के लिए 10 लाख रुपये मिलेंगे जबकि चिराग और सात्विक को पिछले महीने टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए 7.5 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रमण्डल खेलों में रजत पदक विजेता 10 सदस्यीय मिश्रित टीम को कुल 30 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।

US Open : प्लिस्कोवा और सबालेंका क्वार्टरफाइनल में पहुंचा



न्यूयॉर्क।

चेक गणराज्य की 22वीं वरियता प्राप्त सीड कैरोलीना प्लिस्कोवा ने यूएस ओपन के चौथे

दौर में 26वीं वरियता प्राप्त सीड विक्टोरिया अज़ारेका को मात देकर क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली। यूएस ओपन 2016 के फाइनल में एंजलीक केर्बेर से हारने

सबालेंका से होगा। जो सेट में वापसी करके अमेरिका की डेनिएल कॉलिन्स को 3-6, 6-3, 6-2 से हराकर दूसरे यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है।



विराट बतायें किस खिलाड़ी का संदेश चाहते थे : गावस्कर

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि विराट कोहली को उस खिलाड़ी का नाम सार्वजनिक करना चाहिये जिससे वह संदेश का इंतजार कर रहे थे। विराट ने इससे पहले कहा था कि जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी तो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा किसी भी अन्य खिलाड़ी ने उन्हें कोई संदेश नहीं भेजा था। इसपर अब गावस्कर ने सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें उस खिलाड़ी का नाम बताना चाहिए जिससे वह टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद फोन करने की उम्मीद कर रहे थे। गावस्कर ने कहा, यह कहना बहुत कठिन है कि विराट किसका जिक्र कर रहे हैं? अगर उन्होंने कोई नाम लिया होता तो आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि आपने उससे संपर्क किसलिए नहीं किया। मैंने जो सुना है वह यह है कि वह केवल यह कह रहा है कि टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद केवल धोनी ने उन्हें फोन किया। उन्होंने कहा, अगर वह पूर्व खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहा है जो उसके साथ खेले हैं तो उसे उस खिलाड़ी का नाम बताना चाहिए जिसका वह जिक्र कर रहा है। इसके बाद उसे खिलाड़ी से पूछना चाहिये कि उसने संदेश क्यों नहीं भेजा। गावस्कर ने साथ ही कहा कि विराट कोई संदेश चाहते थे या प्रोत्साहन। अगर उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी तो उसे प्रोत्साहन की जरूरत क्या पड़ गयी थी। गावस्कर ने कहा कि जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बेन्सन एंड हेजेस विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप जीतने के बाद कप्तानी छोड़ी तो उनके लिए भी कोई विशेष संदेश या फोन नहीं आया था। तब हमने केवल जश्न मनाया था।

फ्रांसेस टियाफो ने नडाल के विजय अभियान पर लगाई रोक

न्यूयॉर्क:

फ्रांसेस टियाफो ने राफेल नडाल का ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में पिछले 22 मैचों से चला आ रहा विजय अभियान थाम कर पहली बार अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। टियाफो ने आर्थर ऐस स्टेडियम में खेले गए चौथे दौर के मुकाबले में नडाल को 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 से हराया। इस जीत से अभिभूत टियाफो ने कहा, 'मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया थम गई है। एक मिनट के लिए मैंने कुछ नहीं सुना।' टियाफो अभी 24 वर्ष के हैं और उन्हें अमेरिकी ओपन में 22वीं वरियता दी गई है। वह एंडी रोडिक (2006) के बाद इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के अमेरिकी खिलाड़ी हैं। टियाफो का सामना अब आंद्रे रुबलेव से होगा, जिन्होंने सातवीं वरियता प्राप्त कैमरन नोरी को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। नडाल ने इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन और जून में फेंच ओपन का खिताब जीता था। इसके बाद उन्होंने जुलाई में विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी लेकिन पेट को मांसपेशियों में खिंचाव के कारण वह टूर्नामेंट से हट गए थे। अमेरिकी ओपन में चार बार के चैंपियन नडाल इसके बाद केवल एक टूर्नामेंट में खेल पाए थे।



एकदिवसीय क्रिकेट की लोकप्रियता घट रही : मैकग्रा

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने कहा है कि टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट उनके लिए सबसे ऊपर हैं। मैकग्रा ने कहा कि टेस्ट की तरह ही एकदिवसीय क्रिकेट की लोकप्रियता भी कम हो रही है जिससे बनाये रखना क्रिकेट अधिकारियों की जिम्मेदारी है। मैकग्रा के अनुसार क्रिकेटर की असली परीक्षा टेस्ट क्रिकेट में ही होती है। मैकग्रा ने कहा, 'मैं पंपिंग में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे टेस्ट क्रिकेट और एकदिवसीय क्रिकेट से प्यार रहा है। टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए सबसे अहम है। मैं उम्मीद करता हूँ हम इसका सम्मान करेंगे। जहां तक एकदिवसीय क्रिकेट का सवाल है, यह तब तक रोमांचक रहता है जब तक लोग रन बनाते हैं। एकदिवसीय का भविष्य कैसा होगा यह समय आने पर पता चलेगा। इसे रोमांचक रखना एक हमारे लिए चुनौतीपूर्ण बात है।' मैकग्रा का मानना है कि अगर किसी एक प्रारूप में खेलना हो तो आजकल के युवा क्रिकेटर एकदिवसीय क्रिकेट की जगह टी20 क्रिकेट ही खेलना चाहेंगे। उन्होंने कहा, 'अगर आप देखें तो कुछ समय से कई देश एकदिवसीय और टी20 में अलग टीमें रखने लगे हैं। टी20 क्रिकेट में पैसा भी अधिक है। इसलिए भविष्य में अधिकतर युवा खिलाड़ी टी20 क्रिकेट ही खेलना पसंद करेंगे।'



विराट के आरोपों से हैरान बीसीसीआई

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को उस बयान से हैरान है जिसमें उन्होंने कहा था कि कप्तानी छोड़ने के बाद उन्हें केवल महेंद्र सिंह धोनी का ही संदेश मिला था। अब बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोहली को सभी का समर्थन मिला था। अब उन्होंने इस प्रकार की बातें क्यों कही हैं यह हमें समझ नहीं आ रहा। अब बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, 'विराट को सभी से समर्थन मिला है। बीसीसीआई से लेकर साथी खिलाड़ियों ने उन्हें सहयोग दिया है। इस अधिकारी ने कहा कि उन्हें समर्थन नहीं मिलने की बात गलत है। जब भी उन्होंने आराम मांगा उन्हें दिया गया। जब उन्होंने टेस्ट कप्तानी छोड़ी थी, तब बीसीसीआई के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं दी थीं। इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कि वह किस बारे में और क्यों ऐसा बोल रहे हैं।' इस अधिकारी ने कहा, 'कोहली के साथ बोर्ड के कोई मतभेद नहीं हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए जो योगदान दिया है, उसके लिए सभी उनका सम्मान करते हैं। तीनों प्रारूपों में वह बेहतरीन और अहम खिलाड़ी हैं।



केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील, राज्यों के साथ मिलकर स्कूलों को अपग्रेड करने की बनाएं योजना

नई दिल्ली, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि अगले पांच साल में 10 लाख सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण करने के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर एक योजना तैयार करें। मोदी ने सोमवार को पीएम-श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूल विकसित एवं उन्नत करने की घोषणा की थी। योजना के तहत इन स्कूलों को प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालयों और खेल सुविधाओं समेत आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया जाएगा। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन सिर्फ 14,500 स्कूलों का आधुनिकीकरण करना समुद्र में पानी की एक बूंद की तरह है। इस हिसाब से देश के सभी 10.5 लाख स्कूलों को सुधारने में 70-80 साल लगेंगे। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से देशभर के 10.5 लाख स्कूलों को आधुनिक बनाने की अपील करता हूँ।

केजरीवाल ने कहा कि भारत तब तक दुनिया का नंबर एक देश नहीं बन सकता जब तक कि वह हर बच्चे के लिए अच्छी गुणवत्ता, मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित नहीं कर देता। उन्होंने कहा, मैं अक्सर कहता हूँ कि भारत को दुनिया का नंबर एक

देश बनाने के लिए कई काम करने की जरूरत है। जब तक देश के प्रत्येक बच्चे के लिए अब्जल दर्जे की निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता। केजरीवाल ने कहा, भारत को आजादी मिलने के बाद एक बड़ी गलती हुई। हमें देश के हर गांव और कोने में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था और स्कूल सुनिश्चित करने चाहिए थे। अगर हर कोई शिक्षित होता, तो भारत एक गरीब देश नहीं होता।

आम आदमी पार्टी (आप) के मेक इंडिया नंबर-1 अभियान की शुरुआत वह बुधवार को अपने जन्म स्थान हिसार (हरियाणा) से करेंगे और उसके बाद आंदोलन से लोगों को जोड़ने के लिए अन्य राज्यों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी इस अभियान से जुड़ना चाहता है वह 9510001000 पर कॉल कर सकता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का आधार बढ़ाने की योजना के तहत आप प्रमुख ने इस अभियान की घोषणा की है।

केजरीवाल ने कहा, हम आजादी के 75 साल बाद भी पिछड़े हुए हैं। 130 करोड़ लोगों का सपना है कि भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश बने। उन्होंने कहा कि भारत अपने राजनेताओं के कारण विकसित नहीं हुआ और जब तक लोग एकजुट



नहीं होंगे और एक टीम व परिवार के रूप में काम नहीं करेंगे, तब तक चीजें नहीं बदलेगी। अगर ऐसा होता है तो कोई ताकत भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनने से नहीं रोक सकती।

मोदी ने सोमवार को कहा था कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) के तहत नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना को समाहित करते हुए आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा था, आज, शिक्षक दिवस पर मैं एक नयी पहल की घोषणा कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को विकसित व उन्नत किया जाएगा। ये सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीएम-श्री स्कूल देश भर के लाखों छात्रों को फायदा पहुंचाएंगे।

आज 12 देशों के राजनयिकों से मुलाकात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा

नई दिल्ली, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को 'भाजपा को जानो' कार्यक्रम के तहत भारत में तैनात बारह देशों के राजदूतों एवं उच्चायुक्तों के साथ मुलाकात करेंगे।

'भाजपा को जानो' कार्यक्रम के तहत दुनिया के विभिन्न देशों तक उनके राजदूतों या उच्चायुक्तों के माध्यम से भाजपा के इतिहास, संघर्ष, सफलता, विचारधारा और योगदान के बारे में जानकारी पहुंचाने के अभियान की कड़ी में नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बुधवार को शाम चार बजे 12 देशों के राजनयिकों (मिशन के प्रमुख) के साथ संवाद करेंगे।

आपको बता दें कि, भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर इसी वर्ष 6 अप्रैल 2022 को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 'भाजपा को जानो' अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के साथ संवाद कर नड्डा उन्हें भाजपा के इतिहास, संघर्ष, सफलता, विचारधारा और देश एवं समाज के प्रति दिए गए योगदान के बारे में विस्तार से बताते हैं।

बातचीत के दौरान, नड्डा विदेशी राजनयिकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी देते हैं। बुधवार को इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौधवाले के साथ ही पार्टी



के कई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले चार विभिन्न चरणों में नड्डा 47 देशों के राजनयिकों के साथ मुलाकात कर चुके हैं। बुधवार को होने वाली मुलाकात इसी कड़ी की पांचवीं मुलाकात है।

मारवाड़ी युवा मंच की अनूठी पहल बेटियों के सुस्वास्थ्य के लिए पिता ने रखा व्रत



संजय अग्रवाल
रंगो, 06 सितम्बर। पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच की अनोखी पहल पर पिताओं ने अपनी बेटियों के उज्वल भविष्य, स्वस्थ निरोगी काया एवं सुशाहल जीवन के लिये चार सितम्बर को राधा अष्टमी के दिन शुभ मंगला व्रत का भव्य आयोजन किया। प्रांत की शाखाओं ने भव्यतम समारोह के साथ इस व्रत का पालन किया।

पिता भाइयों ने अपनी बेटियों बहनों के लिए दिनभर फलाहारी एवं बिना नमक का व्रत किया एवं सूर्यास्त के बाद बेटों को टीका लगाने के बाद अपनी बेटियों के हाथों से मिठाई खाकर व्रत का पारण किया। प्रांतीय अध्यक्ष आशीष अग्रवाल एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद शाह

ने भी अपनी बेटियों के लिए व्रत रखा। प्रांत के उपाध्यक्ष, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्यों ने भी शुभ मंगला व्रत का पालन किया। अनेक शाखाओं के सदस्यों ने सामूहिक व्रत पारण कार्यक्रम रखा और दीपावली जैसा महोत्सव मनाया और बेटियों को महत्वपूर्ण महसूस करवाया।

लगभग 350 पिताओं ने इस व्रत का समुचित पालन किया और सहर्ष बेटियों से पारण करने के बाद उपहार भी दिया। अनेक बेटियों ने भी व्रत पारण करके अपने पिता को उपहार दिया। राधा रानी के रूप में सभी बेटियों का उत्साह देखने योग्य था। घरों में भी इस व्रत का पारण उत्साह पूर्वक पालन किया गया। माताओं ने भी इस कार्यक्रम में स्वेच्छ से भाग लिया तथा बेटियों

की मंगलकामना के लिये व्रत का पालन किया। जिन अभिभावकों के बेटियां नहीं हैं, उन्होंने अपनी बहनों एवं परिवार की अन्य बेटियों के लिये व्रत रख इस नयी पहल को स्वीकारा है।

पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच की इस अनूठी पहल को महाराष्ट्र प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ने भी सराहा एवं इस पहल में सहयोग कर महाराष्ट्र में अपनी शाखाओं में इस व्रत को करवाया। शुभ मंगला व्रत के समर्थन में 330 से अधिक पिताओं एवं भाइयों ने गूगल फॉर्म भर कर व्रत करने का संकल्प लिया। समाज व इतर समाज के लोग बेटियों के लिये व्रत करने के इस पहल को नारियों के प्रति चेतना लाने की दिशा में एक अच्छी पहल मान रहे हैं।

व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और कुर्सी के लोभ में हर दरवाजे पर जा रहे हैं नीतीश कुमार : रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पटना साहिब से लोक सभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है।

भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लगे नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पटना साहिब से लोक सभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और कुर्सी के लोभ में फंस कर नीतीश कुमार हर एक के दरवाजे पर जा रहे हैं।

रविशंकर प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और विपक्षी दलों में पहले से ही कई नेता इसके लिए खड़े हैं और अब नीतीश कुमार भी खड़े हो रहे हैं।

प्रसाद ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात पर लिखा, नीतीश जी!



राहुल गांधी के साथ आपकी मुस्कुराती तस्वीर टीवी और अखबारों में देखी। सोचा आपको स्मरण कराऊं कि आप तो डा राम मनोहर लोहिया के शिष्य हैं जो गैर कांग्रेसवाद के पहले प्रवर्तक थे। आज कहाँ चले गए आप ?

प्रसाद ने नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर कटाक्ष करते हुए अगले ट्वीट में लिखा, ये जो हर एक के दरवाजे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़े लोग भी घूम चुके हैं पर नतीजा कुछ नहीं निकला। ये कौन सी आपकी महत्वाकांक्षा जाग गई

है? प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और बहुत से दावेदार विपक्ष में पहले से ही खड़े हैं। आप भी खड़े हो जाएं।

नीतीश कुमार पर कुर्सी के लोभ में फंसने का आरोप लगाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने अगले ट्वीट में कहा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और कुर्सी के लोभ के लिए जिस प्रकार से नीतीश जी दिल्ली में प्रयासरत दिख रहे हैं, यदि इतना ही प्रयास बिहार में विकास के प्रोजेक्ट और उद्योगों को लाने के लिए किया होता तो आज बहुत से बिहारी युवाओं को रोजगार मिला होता।

गुजरात विस चुनाव के लिए टिकट बंटवारे में युवाओं, महिलाओं को प्राथमिकता देगी कांग्रेस

अहमदाबाद, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देगी। पार्टी की राज्य इकाई की स्त्रीनिग कमेटी के अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य के चुनावों में 'नए चेहरों' को भी मौका देगी।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस साल दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों की छंटनी करने के लिए पिछले महीने तीन सदस्यीय स्त्रीनिग कमेटी का गठन किया था। चेन्नीथला को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शिवाजीराव मोघे और दिल्ली के पूर्व विधायक जय किशन इसके सदस्य हैं।

गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष जगदीश ठाकोर और नेता प्रतिपक्ष सुखराम राठवा स्त्रीनिग कमेटी के पदेन सदस्य हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को अहमदाबाद में बृथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, जिसके बाद शाम को स्त्रीनिग कमेटी के सदस्यों ने कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति के साथ एक संयुक्त बैठक की, जिसमें शर्मा और ठाकोर सहित 39 सदस्य शामिल हुए।

चेन्नीथला ने मंगलवार को स्त्रीनिग कमेटी की एक और बैठक से पहले संवाददाताओं से कहा, इस बार, हम टिकट वितरण में नए चेहरों, युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देगे। इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए हमारे उम्मीदवारों की सूची प्रभावशाली होगी। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा, कल हुई संयुक्त

बैठक एक-दूसरे से परिचित होने और उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए लागू किए जाने वाले विभिन्न मानदंडों पर चर्चा करने को लेकर थी।

चेन्नीथला ने कहा कि मंगलवार को उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने से पहले जमीनी स्थिति को समझने के लिए, स्त्रीनिग कमेटी वरिष्ठ नेताओं और प्रत्येक विधानसभा सीट के पार्टी प्रभारी से मुलाकात करेगी।

कांग्रेस गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए सितंबर के अंत तक अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर सकती है। आम आदमी पार्टी (आप) पहले ही 19 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। सतारूद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है।

मिशन 2024 की रणनीति पर नड्डा और शाह ने किया केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा नेताओं के साथ मंथन

नई दिल्ली, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। लोकसभा चुनाव में भले ही डेढ़ वर्ष से अधिक का समय बचा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अभी से अपनी तैयारियों और रणनीति को अमली जामा पहनना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बी एल संतोष ने 144 लोकसभा सीट पर पार्टी को और मजबूत करने और इनमें से अधिकतर पर जीत सुनिश्चित करने संबंधी संभावित कवायद को लेकर केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा की।

यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि यह ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा आरंभ होने वाली है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा विरोधी सभी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, भाजपा नेताओं की बैठक में उन 144 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति को लेकर चर्चा की गई, जिन (सीट) पर भाजपा पिछले चुनाव में मामूली अंतर से चूक

गई थी। इनमें वे निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा दूसरे या तीसरे स्थान पर रही थी या जिन पर उसने कभी जीत दर्ज की ही नहीं है। इन सीटों को समूहों में बांटा गया है और प्रत्येक समूह का प्रमुख एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया गया है।

भाजपा मुख्यालय में हुई इस बैठक में पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी, गजेंद्र सिंह शेखावत, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, अनुपम ठाकुर, किरन रीजू, जी किशन रेड्डी सहित 25 से अधिक केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान इन मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले निर्वाचन क्षेत्रों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की।

सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों ने लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया है और चुनावी रूप से महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की है। सूत्रों के मुताबिक इन मंत्रियों ने जो रिपोर्टें काई तैयार किया है, उसमें इन संसदीय क्षेत्रों में पार्टी की मजबूती, कमजोरियां, अवसरों और चुनौतियों पर विशेष बल दिया है और साथ ही सुझाव भी दिए हैं कि कैसे इन सीट पर पार्टी 2024 में जीत दर्ज कर सकती है।

पार्टी ने इसके लिए धर्म, जाति, भौगोलिक स्थिति और मतदाताओं के रूझान को लेकर एक रूपरेखा



भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, शाह ने दी गई जिम्मेदारी के अनुसार मंत्रियों द्वारा संसदीय क्षेत्रों का दौरा ना करने पर अप्रसन्नता जताई और ऐसे मंत्रियों से कहा कि संगठनात्मक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक सूत्र ने बताया, संदेश साफ था (शाह का) कि पार्टी संगठन के काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, शाह ने नेताओं से कहा कि संगठनात्मक मजबूती में यदि किसी प्रकार की खामी रहेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकेगा। नड्डा ने भी मंत्रियों से संगठनात्मक जिम्मेदारियों को पूरा करने की

असली शिवसेना पर सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई, शिंदे गुट ने लगाई है अर्जेंट हियरिंग की गुहार



नई दिल्ली, 06 सितम्बर (एजेन्सी)। महाराष्ट्र में असली शिवसेना किसकी है, इस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कल इस मामले की लिस्टिंग हो सकती है। गौरतलब है महाराष्ट्र में असली शिवसेना को लेकर लंबे समय से सुनवाई लंबित है। अब महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने शीर्ष कोर्ट के सामने इस मामले की अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बीएमपी चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। इसको देखते हुए शिंदे गुट चाहता है कि असली शिवसेना पर जल्द से जल्द फैसला हो।

मंगलवार को एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने इस मामले में अर्जेंट हियरिंग की गुहार लगाई है। इसके बाद सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि वह बुधवार को इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर सकते हैं। सीजेआई यूयू ललित ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन कल कुछ न कुछ तो होगा जरूर। वहीं मामले की अर्जेंट सुनवाई की बात करते हुए सीनियर एडवोकेट कौल ने कहा कि शीर्ष कोर्ट ने पांच जजों की संवैधानिक बेंच को मामला रेफर किया था। वहीं चुनाव आयोग में भी इस मामले की सुनवाई रुक गई थी।

एडवोकेट कौल ने कहा कि अब जबकि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। गौरतलब है कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने इस मामले की याचिका को पांच जजों की संवैधानिक पीठ को सौंप दिया था। उस वक इस मामले की सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय हुई थी। लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई पेंडिंग ही है। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया था कि 25 अगस्त तक वह असली शिवसेना पर फैसला न सुनाए। उसने यह आदेश शिंदे गुट द्वारा खुद को असली शिवसेना बताने की याचिका पर दिया था।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना को लेकर संघर्ष लगातार जारी है। खुद को असली शिवसेना बताकर शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट पार्टी की विभिन्न परंपराओं पर रावा ठोक रहे हैं। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर भी दोनों गुटों में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। वहीं बीएमपी चुनाव को लेकर भी गहमागहमी तेज हो चली है। यहां पर भाजपा बीएमपी पर शिवसेना के लंबे वर्चस्व को खत्म करने की तैयारी में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी बीएमपी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान शाह ने तो उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने तक की बात कह डाली थी।